राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 22 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-200 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## पहला कॉलम



## वंदे मातरम पर कांग्रेस में कलह- 2 स्टैंजा के फैसले पर पार्टी के भीतर ही उठे सवाल

**-कार्यसमिति ने दोहराया फैसला तो सिंघवी ने दिया कानूनी तर्क**

**नई दिल्ली।**

वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का अपना फैसला अब पार्टी के भीतर ही सवालों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) ने पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत की सिर्फ पहले दो पैराग्राफ गाने के फैसले को दोहराया है, जिसके बाद पार्टी के कुछ नेताओं में बेचैनी है। कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने अनजाने में बीजेपी को वही मुद्दा दे दिया, जिस पर वह सबसे ज्यादा सहज तरीके से राजनीतिक हमला कर सकती है। कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस विवाद में कानूनी पहलू सामने रखा है। उनका कहना है कि कानून उसकी मौजूदा स्थिति के हिसाब से देखा जाना चाहिए और उन्होंने सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रमों के बीच अंतर बताया। सिंघवी के मुताबिक, मौजूदा कानून सरकारी आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के गायन से जुड़ी बात करता है, पार्टी के आंतरिक कार्यक्रमों के बारे में उसमें वैसी स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। कार्यसमिति के ही एक सदस्य ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे को बीजेपी की ताकत नहीं बनाना चाहिए था, जबकि छात्रों के मुद्दे और चंदा चोरी जैसे ज्यादा अहम मुद्दे मौजूद हैं। सीडब्ल्यूसी ने अपने फैसले के समर्थन में 1937 के प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने वंदे मातरम की पहले दो पैराग्राफ के गायन का समर्थन किया था।

## पैलेट गन विवाद- राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे

**- कहा- एफआईआर दर्ज होने के बाद ही हटेंगे**

**नई दिल्ली।**

दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उठे गंभीर विवाद के बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, वे अपनी जगह से नहीं हटेंगे। उनके साथ पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लाछोब और उसका परिवार भी मौजूद है, जिसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है। राहुल गांधी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने भी 20 जुलाई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गृह मंत्री को देश को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत दी थी या नहीं। कांग्रेस का मानना है कि इस पूरे मामले को उजागर करना और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करना बेहद ज़रूरी है। इस बीच, इस संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल के प्रयोग की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में यह समिति जांच करेगी कि क्या पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान आवश्यकता से अधिक या अनुचित बल का प्रयोग किया। इसमें पैलेट गन, बिजली के डंडे, लाठी और आंसू गैस के इस्तेमाल की परिस्थितियों की गहन जांच की जाएगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि पुलिस की कार्रवाई उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप थी या नहीं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बीच उचित संतुलन स्थापित किया गया था या नहीं। इसके अतिरिक्त, समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट या अन्य धातु के प्रोजेक्टाइल के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं।

## कार की टक्कर से महिला की मौत, सांसद के बेटे पर केस

**हैदराबाद।**

हैदराबाद के माधापुर इलाके में 16 अगस्त को हुए सड़क हादसे में 26 वर्षीय महिला की मौत मामले में पुलिस ने आंध्र प्रदेश से जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति लिंगमानेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे लिंगमानेनी संजुश को आरोपी बनाया है। पुलिस ने उसे नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

माधापुर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सी. श्रीधर ने मीडिया को बताया कि मामले में संजुश को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह जमानती अपराध है और इसमें अधिकतम सजा सात साल से कम है। पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त को माधापुर इलाके में कार की टक्कर से 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। घटना के बाद मामले की जांच शुरू की गई और जांच के दौरान सांसद के बेटे का नाम सामने आया। इसके आधार पर पुलिस ने उसे आरोपी बनाया और कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

# राष्ट्रपति भवन ने चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी को रद्द करने का आदेश वापस लिया

**नई दिल्ली।**

राष्ट्रपति भवन ने अपना फैसला बदलते हुए कुछ ही घंटों में वह आदेश वापस ले लिया, जिसके तहत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के औपचारिक स्वागत की फुल रिहर्सल के लिए शनिवार को फोरकोर्ट में होने वाली गार्ड बदलने की रस्म को रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन के बयान वापस लेने को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई दिल्ली यात्रा को लेकर अनिश्चितता के तौर पर देखा जा रहा है। समारोह को रोकने की घोषणा के बाद, राष्ट्रपति भवन ने दोपहर में एक नया बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि शुक्रवार को इस शनिवार को गार्ड बदलने का समारोह नहीं होगा विषय पर जारी प्रेस विज्ञप्ति को वापस ले लिया गया है। आमतौर पर, राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में 30 मिनट का गार्ड बदलने का समारोह हर शनिवार सुबह आयोजित किया जाता है। अगर शनिवार को कोई सरकारी छुट्टी हो या राष्ट्रपति भवन द्वारा ऐसा सूचित किया जाए, तो यह समारोह आयोजित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति भवन के अनुसार, गार्ड बदलने का समारोह एक सैन्य परंपरा है। इसके तहत फोर्ट, पैलेस और रक्षा प्रतिष्ठानों पर गार्ड और संतरी समय-समय पर बदलते रहते हैं ताकि सैनिकों की एक नई टुकड़ी कार्यभार संभाल सके। राष्ट्रपति भवन में, सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन भारत के राष्ट्रपति के लिए औपचारिक गार्ड और संतरी उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। समारोह को और अधिक आकर्षक और जनता के अनुकूल बनाने के लिए इसमें बदलाव किए गए हैं और इसका स्थान भी बदला गया है। इसमें राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स (पीबीजी) द्वारा अपनी औपचारिक पोशाक में घुड़सवारी का प्रदर्शन शामिल किया गया है।

साथ ही, समारोह स्थल को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां जनता की पहुंच आसान है। समारोह की शुरुआत पीबीजी सैनिकों द्वारा होती है, जो अपने सजे-धजे घोड़ों पर सवार होकर



जयपुर कॉलम के पीछे से आगे बढ़ते हैं। इस दौरान आर्मी ब्रास बैंड धुन बजाता है। इसके बाद, परेड कमांडर मार्च करते हुए आते हैं और उनके कमांड पर गार्ड मार्च करते हैं।

निरीक्षण के बाद, नया गार्ड पुराने गार्ड के साथ अपनी जगह लेता है और दोनों गार्ड राष्ट्रीय सलामी का आदान-प्रदान करते हैं। इसके बाद, नया गार्ड, गार्ड और संतरी की ड्यूटी संभालता है। समारोह का समापन पीबीजी द्वारा घुड़सवारी के प्रदर्शन और राष्ट्रगान के साथ होता है।

## पीएम मोदी ने सुभाषित में लिखा- अपना जीवन दूसरों की सेवा-कल्याण के लिए समर्पित करो

**नई दिल्ली।**

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शुक्रवार को सुभाषित शेयर किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा- नदियों का अविरल प्रवाह सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए कर सकते हैं। निःस्वार्थ सेवा, समर्पण और परोपकार की यही भावना राष्ट्र को नई दिशा देती है। पीएम मोदी की ओर से एक संस्कृत श्लोक, जीवनं स्वं परार्थाय नित्यं यच्छत मानवाः। इति सन्देशमाख्यातुं समुद्रं यान्ति निम्नगाः॥ साझा किया, जिसका हिंदी अर्थ है- हे मनुष्यों! अपना जीवन सदैव दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित करो, जिस प्रकार नदियां बिना किसी स्वार्थ के निरन्तर बहती हुई अपने जल से मार्ग में आने वाले असंख्य प्राणियों का जीवन पोषित करती हैं और अन्ततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन और सामर्थ्य का इस्तेमाल दूसरों के हित में करना चाहिए। निःस्वार्थ सेवा, परोपकार और लोककल्याण में ही मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है।

पीएम मोदी की ओर से बीते दिन सुभाषित में एक संस्कृत श्लोक, आपत्काले च कष्टेऽपि नोत्साहस्त्यज्यते बुधैः। इति प्रबोधितस्तेन कथञ्चिद् दृढबुद्धिना। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसका अर्थ है- स्थिर और दृढ़ बुद्धि वाले ज्ञानीजन समय आने पर यह समझाते हैं कि बुद्धिमान लोग संकट और कठिन परिस्थितियों में भी कभी अपना उत्साह नहीं खोते। सुभाषित शेयर करते हुए पीएम मोदी की ओर से संदेश दिया गया था कि सदैव परोपकार एवं कल्याणकारी कर्म ही करें।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था- एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु। प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा॥ इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है, इस



संसार में मनुष्यों के जन्म की पूर्ण सार्थकता इसी में निहित है कि वे अन्य प्राणियों के प्रति अपने शारीरिक सामर्थ्य, धन-संपत्ति, बुद्धि और वाणी के जरिए सदैव परोपकार एवं कल्याणकारी कर्मों का ही सम्पादन करें।

## मंत्री के खिलाफ विधायकों ने खोला मोर्चा

**नई दिल्ली।**

तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के 18 विधायकों और एमएलसी ने मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुरेखा को पार्टी से निलंबित या बाहर करने की मांग की। इन नेताओं को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के समर्थक गुट का माना जा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि कोंडा सुरेखा समेत कुछ वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान से ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। वारंगल वेस्ट से विधायक नाइनी राजेंद्र रेड्डी ने कोंडा सुरेखा पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के ही कुछ लोग सुरेखा का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस छोडने् के लिए कह रहे हैं।

## देश के निर्यातक अब भारतीय मुद्रा में कर सकेंगे सौदे

**- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये को नई उड़ान**

**नई दिल्ली।**

भारतीय निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने विदेशी व्यापार के नियमों में संशोधन करते हुए अब भारतीय निर्यातकों को हर सौदे में डॉलर या किसी अन्य विदेशी मुद्रा में भुगतान लेने की अनिवार्यता से मुक्ति दे दी है। वे कई देशों के साथ भारतीय रुपये में भी निर्यात अनुबंध और इनवॉयस तैयार कर सकेंगे और निर्धारित नियमों के तहत भुगतान रुपये में प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारतीय मुद्रा को वैश्विक स्वीकार्यता मिल सके। महानिदेशालय सामान्य विदेशी व्यापार (डीजीएफटी) ने 20 अगस्त को विदेश व्यापार नीति 2023 में यह संशोधन किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वर्ष 2023 में जारी विदेशी मुद्रा संबंधी नियमों के अनुरूप है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र निर्यात के बदले अधिकृत बैंकिंग चैनलों से प्राप्त रुपये के भुगतान को अब विदेश व्यापार नीति के तहत मिलने वाले लाभ और निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए भी मान्यता दी जाएगी। यह निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि पहले केवल विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतानों को ही इन लाभों के लिए योग्य माना जाता था। अब तक, भारतीय कंपनियाँ मुख्य रूप से डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी प्रमुख विदेशी मुद्राओं में ही भुगतान प्राप्त करती रही हैं। इससे मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ता था, जो निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा करते थे। रुपये में व्यापार की अनुमति पहले भी कुछ विशेष परिस्थितियों में थी, लेकिन नियमों और उससे मिलने वाले लाभ को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं थी। नए बदलावों से इस व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और ठोस आधार मिलने की उम्मीद है, जिससे इसका उपयोग अधिक सुलभ और आकर्षक हो जाएगा। नए नियमों के तहत, एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) से बाहर के देशों के साथ भारतीय निर्यातक रुपये या किसी विदेशी मुद्रा में निर्यात अनुबंध और इनवॉयस तैयार कर सकेंगे। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर विदेशी खरीदार अब रुपये में भुगतान करेगा, बल्कि यह एक विकल्प है जहाँ दोनों पक्ष सहमत हों और निर्धारित बैंकिंग तथा नियामकीय शर्तें पूरी हों। रुपये में भुगतान स्वीकार करने से कुछ मामलों में मुद्रा बदलने की लागत और विदेशी मुद्रा से जुड़े जोखिम कम



हो सकते हैं, जिससे निर्यातकों के लिए लेनदेन अधिक कुशल बन सकता है। यह उन देशों के साथ व्यापार में भी सुविधा प्रदान कर सकता है जहाँ डॉलर के माध्यम से भुगतान करना मुश्किल होता है या जहां डॉलर की उपलब्धता सीमित है। नेपाल और भूटान के साथ रुपये की भूमिका पहले से ही स्थापित है और वहां के लिए यह नियम अलग हैं, जबकि एसीयू के सदस्य देशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित नियम लागू रहेंगे। इसके अलावा, सरकार या एक्जिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत होने वाले निर्यात में भी भारतीय रुपये में इनवॉयस की व्यवस्था की जा सकती है।

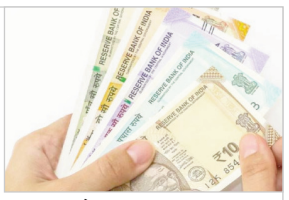

## सिखों की रिहाई के लिए 7 घंटे पंजाब बंद

**हाईवे के साथ पिज्जा शॉप-क्लब बंद कराए, पुलिस-प्रदर्शनकारियों में बहस**

**चंडीगढ़/मोहाली।**

कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद रखा गया।

मोर्चा सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद सिखों की रिहाई और पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग कर रहा है। बंद के दौरान बसों के साथ सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे। हालांकि ट्रेनों पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। खरड़-चंडीगढ़ हाईवे को बंद किया गया था।

यहां ड्यूटी पर जाने वाले लोगों की मोर्चा के सदस्यों से बहस भी हुई।

मोहाली में निहंगों ने पिज्जा शॉप बंद कराई। इसे साथ अमृतसर, पटियाला और लुधियाना में कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने खुली दुकानों को बंद करवाया। इससे पटियाला में माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

जालंधर में प्रदर्शनकारी ने कार सवार को थप्पड़ मार दिया था। कार सवार अस्पताल जा रहा था। रास्ते में रोकने को लेकर विवाद हो गया। वहीं, फरीदकोट में प्रदर्शनकारियों ने आप विधायक डिंपी ढिल्लों की बस को रोक दिया था।

बस को रोके जाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसे वापस बस स्टैंड भेज दिया। अमृतसर और मोहाली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई।

इस बीच चंडीगढ़ भाजपा के स्टेट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल में पंजाब बंद रखने और बंद के दौरान खुले रहने वाले शहरों में बम धमाके करने का भी जिक्र था। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और जांच शुरू की।

## नरवणे का अहम बयान-पाकिस्तान आज की चिंता,चीन कल की बड़ी चुनौती

**पूर्व थलसेना प्रमुख बोले–बातचीत का रास्ता खुला रखें, मगर हर चुनौती के लिए सैन्य शक्ति और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता भी जरूरी**

**मुंबई ।**

भारत के पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की सामरिक चुनौतियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अपनी नई पुस्तक के विमोचन के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियां भारत के सामने तात्कालिक सुरक्षा चुनौती रणनीतिक दृष्टि से चीन भारत का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनकर उभर सकता है। जनरल नरवणे ने चीन के लिए सीधे तौर पर दुश्मन शब्द का प्रयोग करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि भारत को मतभेदों और विवादों के समाधान के लिए बातचीत तथा कूटनीति का रास्ता खुला रखना चाहिए। हालांकि, इसके साथ ही किसी भी संभावित चुनौती और दुस्साहस को रोकने के लिए देश की सैन्य क्षमता तथा प्रतिरोधक शक्ति को लगातार मजबूत बनाए रखना भी

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि भारत के पाकिस्तान और चीन, दोनों के साथ सीमा विवाद और युद्ध का इतिहास रहा है, लेकिन दोनों देशों से मिलने वाली सुरक्षा चुनौतियां अलग प्रकृति की हैं। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को कथित समर्थन मिलने के कारण भारत का तत्काल ध्यान पश्चिमी सीमा की सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित रहता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा केवल सीमा और सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में और सामरिक मामलों समेत कई क्षेत्रों में चीन भारत के सामने एक बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जहां प्रतिस्पर्धा होती है, वहां तनाव और टकराव की संभावना भी बनी रहती है। कूटनीति को प्राथमिकता, सैन्य शक्ति अंतिम सुरक्षा कवच

जनरल नरवणे ने कहा कि विवादों के समाधान के लिए बल प्रयोग के बजाय पहले बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों का सहारा लिया जाना चाहिए। सैन्य शक्ति का उपयोग अंतिम विकल्प होना कि शांति की रक्षा के लिए मजबूत सैन्य तैयारी अनिवार्य है। किसी भी संभावित आक्रामकता को रोकने के लिए प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता जरूरी है। उनके अनुसार, शांति की इच्छा रखने वाले देश को हर संभावित परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

स्थिर और शांतिपूर्ण पड़ोस भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी

पूर्व थलसेना प्रमुख ने भारत के पड़ोसी देशों में शांति और स्थिरता को भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश



साथ स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने पड़ोसियों का चयन नहीं कर सकता, इसलिए क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता बनाए रखने

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

# कब तक जारी रहेगा जहरीली शराब का जानलेवा कहर?

**पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन भावनगर कोई पहली घटना नहीं है।हाल ही में मई माह में महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ त्रासदी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 14 से 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस जांच के अनुसार, अवैध रूप से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड का घातक मेथनॉल मिक्स किया गया था।मई माह में ही पंजाब के अमृतसर के पांच गांवों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात ने जुलाई 2022 में भी भयावह शराब त्रासदी देखी थी।**

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल )

भारत में जहरीली शराब से होने वाली मौतें एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनी हुई हैं, जिसमें ड्राई स्टेट शराबबंदी वाले राज्यों से लेकर अन्य राज्यों तक लगातार दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला अगस्त 2026 में गुजरात के भावनगर का है, जहां नकली विदेशी शराब के नाम पर बेची गई जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

जहरीली शराब का यह जानलेवा सिलसिला देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर देखने को मिलता है एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बना हुआ है। ट्रांसनेशनल अलायंस टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रेड जैसी संस्थाओं के अनुसार, भारत में अवैध शराब की खपत दुनिया के सबसे बड़े अवैध बाजारों में से एक है। यह न केवल सरकारी राजस्व को भारी चोट पहुँचाता है, बल्कि इसके कारण हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।देश भर में आए दिन जहरीली और नकली शराब से होने वाली मौतें अब केवल दुर्घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ये घटनाएं हमारी व्यवस्था, कानून और समाज के सामने एक गंभीर सवाल हैं । कुछ दिन सप्ताह माह के अन्तराल पर देश के किसी न किसी हिस्से से खबर आती है कि नकली शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी, कई अस्पताल पहुंचे और कुछ ने दम तोड़ दिया। प्रशासन सक्रिय होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, जांच बैठती है, मुआवजे की घोषणा होती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। फिर किसी दूसरे शहर, गांव या राज्य में वही कहानी दोहराई जाती है। सवाल यही है, आखिर यह सिलसिला कब थमेगा ?

आपको बता दें कि ताजा मामला गुजरात के भावनगर जिले का है। गुजरात उन राज्यों में है जहां लंबे समय से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भावनगर में कथित नकली शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की घटना सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने चार लोगों की मौत की जानकारी दी थी, जबकि अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था। शुरुआती रिपोर्टों में मौतों की संख्या कम थी, जो बाद में बढ़ी। यह घटना इसलिए भी अधिक गंभीर है, क्योंकि जिस राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर कानूनी प्रतिबंध है, वहां नकली शराब लोगों तक पहुंच कैसे रही है? पुलिस की शुरुआती जांच में एक लोकप्रिय ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट शराब बेचे जाने और इसके मध्य प्रदेश से लाए जाने की आशंका सामने आई है। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन भावनगर कोई पहली घटना नहीं है।हाल ही में मई माह में महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ त्रासदी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 14 से 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस जांच के अनुसार, अवैध रूप से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड का घातक मेथनॉल मिक्स किया गया था।मई माह में ही पंजाब के अमृतसर के पांच गांवों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात ने जुलाई 2022 में भी भयावह शराब त्रासदी देखी थी। बोटाद और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस समय भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अधिकारियों का तबादला हुआ और अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के दावे किए गए थे। सवाल है कि चार वर्ष बाद भी यदि नकली शराब लोगों तक पहुंच रही है तो पिछली कार्रवाई से हमने आखिर सीखा क्या? यह समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य समय-समय पर ऐसी त्रासदियों के गवाह बने हैं। तमिलनाडु के कालाकुरिची में जून 2024 में मेथेनॉल मिली अवैध शराब ने दर्जनों परिवारों को उजाड़ दिया था। आधिकारिक कार्रवाई के दौरान अवैध शराब जब्त हुई, गिरफ्तारियां हुई और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में भी अवैध एवं नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध एनसीआरबी आधारित डेटा 2012 से 2024 तक राज्य वार ऐसी मौतों का हवाला देता है। इससे इतना तो साफ है कि यह किसी एक राज्य या एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक खतरनाक चुनौती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अक्सर इन घटनाओं में मरने वाले लोग समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर वर्ग से आते हैं। सस्ती शराब की तलाश उन्हें ऐसे अवैध कारोबारियों तक पहुंचा देती है जिन्हें न गुणवत्ता की चिंता होती है, न कानून का भय और न इंसानी जीवन की कीमत का एहसास। अधिक नशा पैदा करने या लागत कम रखने के लिए शराब में मेथेनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। कल्लाकुरिची मामले में भी मेथेनॉल मिश्रित शराब की पुष्टि सामने आई थी। अधिकरत देखा जाता है कि हर बड़ी आसदी के बाद प्रशासन की एक परिचित तस्वीर सामने आती है। छापेमारी शुरू होती है, अवैध ठिकाने बंद किए जाते हैं, संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है। लेकिन असली चुनौती घटना के बाद कार्रवाई करने की नहीं, घटना होने से पहले नेटवर्क को समाप्त करने की है। अवैध शराब का कारोबार अकेले किसी गली या गांव में बैठा व्यक्ति नहीं चला सकता। कच्चा माल कहां से आता है? बोतलें कहां बनती हैं? लोकप्रिय कंपनियों के नाम और लेबल की नकल कैसे होती है? माल एक जिले से दूसरे जिले और कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचता है? परिवहन, भंडारण और बिक्री की जानकारी स्थानीय स्तर पर किसी को क्यों नहीं मिलती? यदि वर्षों तक कारोबार चलता रहता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही, स्थानीय संरक्षण या भ्रष्ट तंत्र भी इसका रास्ता आसान कर रहा है। शराबबंदी वाले राज्यों के लिए यह समस्या और बड़ी चुनौती है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। यदि वैध बिक्री बंद होने के बाद अवैध बाजार पैदा हो जाए और उसकी निगरानी कमजोर रहे तो तस्करों को अधिक मुनाफे का अवसर मिलता है। शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशे से बचाना है, लेकिन यदि उसी व्यवस्था के भीतर जहरीली शराब का संगठित बाजार फलने लगे तो नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन दोनों जरूरी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराबबंदी गलत है या शराब की खुली बिक्री समाधान है।

असली प्रश्न नीति से अधिक उसके प्रभावी क्रियान्वयन का है। जहां प्रतिबंध है वहां अवैध सप्लाई पर कठोर निगरानी होनी चाहिए और जहां शराब की कानूनी बिक्री है वहां नकली उत्पादों की पहचान और वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत होना चाहिए। सरकारों को अब प्रत्येक त्रासदी के बाद केवल मुआवजा देने और कुछ लोगों को निलंबित करने से आगे बढ़ना होगा। अवैध शराब के मामलों में सप्लाई चेन की तह तक जांच, औद्योगिक मेथेनॉल की बिक्री और परिवहन की निगरानी, नकली ब्रांड और पैकेजिंग बनाने वालों पर कार्रवाई तथा बार-बार अवैध कारोबार में पकड़े जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है।यह सारा अवैध कारोबार बिना सरकारी तंत्र की मिलीभगत के सम्भव नहीं है स्थानीय पुलिस और आबकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण और गरीब बस्तियों में जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को बताया जाना चाहिए कि अनजान स्रोत से खरीदी गई शराब जानलेवा हो सकती है। संदिग्ध शराब पीने के बाद उल्टी, चक्कर, दृष्टि धुंधली होने वा अन्य परेशानी के मामलों में तुरंत अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। कई बार इलाज में देर भी मौतों की संख्या बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहरीली शराब से हुई हर मौत को महज एक आंकड़ा समझने की मानसिकता बदलनी होगी। मरने वाला किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य, बेटा, पिता या भाई होता है। उसके जाने के बाद परिवार केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक संकट में भी डूब जाता है। देश में तकनीक बड़ी है, पुलिस के पास आधुनिक संसाधन हैं, राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान पहले से आसान हुआ है। ऐसे में यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अवैध शराब की पेटियां एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचे और व्यवस्था को भनक तक न लगे। भावनगर की घटना फिर चेतावनी दे रही है कि नकली शराब केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। कार्रवाई तब सार्थक होगी जब अगली त्रासदी होने से पहले अपराधी नेटवर्क खत्म किया जाए। हर घटना के बाद वही सवाल पूछने की मजबूरी आखिर कब समाप्त होगी, कब थमेगा जहरीली शराब का कहर और कब बंद होगा बेगुनाहों की मौतों का यह सिलसिला। एक मौत पूरे परिवार को मार देती है कई बार परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य की मौत से पूरा परिवार प्रभावित होता है। सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

संपादकीय

## हेल्थकेयर की चुनौतियां

यह विडंबना ही है कि देश में कभी भी सत्ताधीशों की प्राथमिकता सरकारी चिकित्सा-तंत्र को सक्षम बनाने की नहीं रही है। किसी भी चुनाव में स्वास्थ्य सुविधाओं को समृद्ध बनाना राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं रहा। जनता भी हर आम परिवार से जुड़े सेहत के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने में चूकती रही है। यही वजह है कि आज भी कुल मिलाकर देश के करोड़ों लोगों के लिये सस्ती व पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच से बाहर हैं। अपने परिजनों के गंभीर रोगों के उपचार के लिये क्षमता से अधिक पैसा जुटाने के फेर में हजारों परिवार हर साल गरीबी की दलदल में धंस जाते हैं। यह गंभीर स्थिति सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में हेल्थकेयर पर बनी संसदीय समिति की हालिया रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के 2025 के सर्वे का हवाला देते हुए संसदीय समिति ने पाया है कि सरकारी सुविधाओं में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज का औसत खर्च 6,631 रुपये है, जबकि प्राइवेट में यह खर्च 50,508 रुपये है। निजी अस्पताल में होने वाला यह औसत खर्च सरकारी अस्पताल में होने वाले खर्च के मुकाबले सात गुना से भी अधिक है। जो चिकित्सा सुविधाओं में व्याप्त व्यापक विसंगतियों को ही दर्शाता है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है कि निजी अस्पताल अब साठ फीसदी से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करते हैं और 70 फीसदी आउट पेशेंट की देखभाल करते हैं। विडंबना यह है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव लगातार बना रहता है। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी मरीज महसूस करते हैं। सरकारी अस्पताल की सुविधाओं में बेड, उपकरण, दवाइयां और कुशल स्टाफ की कमी देखी जाती है। मरीज को भरोसा नहीं होता है कि उसे जरूरी इलाज सरकारी अस्पताल में मिल भी पायेगा। एक संकट यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में चिकित्सकों की अच्छी आय और निजी प्रैक्टिस का सम्मोहन भी योग्य डाक्टरों को सरकारी अस्पतालों से विमुख बनाता है। यही वजह है कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिये बाध्य होना पड़ता है। दरअसल, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, अब चाहे उनकी पैसा देने की क्षमता हो या न हो। लोगों की चिकित्सा इमरजेंसी की चिंता की वजह से स्वास्थ्य बीमा का बड़ा कारोबार देश में फल-फूल रहा है। जिसमें मरीजों को कम व बीमा कंपनियों और निजी अस्पतालों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। यही वजह है कि आज हेल्थकेयर सिस्टम में इलाज की सुविधा परिवार की आमदनी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है। इसके चलते ही संसदीय पैनल की यह बात खास तौर पर चिंताजनक है कि अस्पताल में भर्ती होने का औसत बिल 37,858 है, जिसमें से मरीज अपनी जेब से लगभग 34,064 रुपये खर्च करते हैं। हालांकि, कुल बिल में अपनी जेब से होने वाला खर्च 2014 के 62.6 फीसदी से घटकर 2022-23 में 43.4 फीसदी हो गया है। इसके बावजूद 10-13 फीसदी की मेडिकल महंगाई का असर परिवारों के बजट पर अब भी पड़ रहा है। लेकिन सरकारी सुविधाओं में आ रही गिरावट को टाला न जा सकने वाला मान लेना भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। शासन-प्रशासन की प्राथमिकता सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की होनी चाहिए। निस्संदेह, संसदीय समिति की सिफारिशें सही दिशा की ओर संकेत देती हैं। इसमें छोटे और ग्रामीण अस्पतालों के लिये लक्षित सहायता, पारदर्शी इलाज पैकेज, बीमा दरों की समय-समय पर समीक्षा, मध्यम आय वाले वर्ग के लिये किफायती बीमा सुविधा, जेनेरिक दवाइयों तक मरीजों की व्यापक पहुंच बनाने तथा शहरों से परे मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है।

# सड़क पर पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, फिर फुटपाथ क्यों बेहाल?

**सच तो यह है कि नींदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन उपलब्ध हैं। नींदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक-शांत क्षेत्र हैं।**

(लेखक -सुनील कुमार महला )

सड़क पर पैदल चलना मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भारत के कई शहरों में पैदल चलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल, आज भी बहुत से शहरों में फुटपाथ या तो बने ही नहीं हैं, या उन पर अतिक्रमण, पार्किंग और निर्माण सामग्री के कारण लोगों के चलने की जगह नहीं बचती। ऐसे में यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल चलने की जगह ही नहीं है, तो उसे वास्तव में आवागमन की आजादी कैसे मिल सकती है?

उक्त संदर्भ में यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही यानी कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा है कि सुरक्षित और निर्धारित पैदल मार्ग पर चलना भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत आवागमन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वास्तव में, यह मामला उस दुखद घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें पांच साल के एक बच्चे की सड़क पर टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहां न फुटपाथ था और न ही सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज कई भारतीय शहरों में फुटपाथ पर अतिक्रमण, टूटे या गायब फुटपाथ, सड़क पार करने के लिए अपर्याप्त क्रॉसिंग, तेज रफ्तार वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हमारे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में 35,221 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 20.4ब्व थी।सच तो यह है कि आज पर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है । यहां पाठकों को बताता चलूं कि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यतः राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के दायरे में आता है, इसलिए सरकारों और संबंधित निकायों को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वैसे विश्व में सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, पैदल पार-पथ, ट्रैफिक नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मामलों में नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। सच तो यह है कि नींदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन उपलब्ध हैं। नींदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक-शांत क्षेत्र हैं। वहीं पर स्वीडन विश्व में कम पैदल मृत्यु दर और मजबूत सड़क-सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्रणी देशों में शामिल है।नॉर्वे(यूरोप में) तथा फिनलैंड भी पैदल मार्गों और सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था के मामले में विश्व में अहम् और महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हाल फिलहाल, यहां यह कहना चाहूंगा कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क पर पैदल चलने के संदर्भ में जो फैसला दिया है,इस फैसले का सीधा सा संदेश यही है कि सरकार और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि ये लोगों को सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराएं। वास्तव में,सच तो यह है कि नगर निगम, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण और पंचायतों को आगे आकर इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना होगा।बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो, आंकड़े हमारी चिंताएं बढ़ाते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक लोग पैदल यात्री होते हैं। कई शहरों में फुटपाथ टूटे हुए, संकरे, असुरक्षित या लगातार बाधित पाए गए हैं। यानी समस्या केवल फुटपाथ बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, चौड़ा, समतल और सभी के लिए सुगम बनाने की है। वास्तव में,इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग न हो, वहां पर पर्याप्त रोशनी हो, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बने और दिव्यांगजनों के लिए रैंप तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क की खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान भी पैदल यात्रियों के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह बात कही जा सकती है कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं। पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांगजन सभी सड़क के बराबर अधिकार रखते हैं। सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार।)

# चैन से सोना है तो सोने को कहें ना

चिंतन मनन

सोने की चमक सभी को आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण लोग अधिक से अधिक सोना खरीदने चाहते हैं। यह चाहत तब और भी बढ़ जाती है जब सोने की कीमत में अचानक थोड़ी गिरावट आती है। लोग इस मौका का लाभ उठाना चाहते हैं। आज कल बाजार में यही स्थिति है क्योंकि सोने की कीमत कमी आयी है। आइए जानें सोने के बारे में हमारे शास्त्रों क्या कहा गया है। ज्यादातर पौराणिक ग्रंथों में इस बात को कई तरह से कहा गया है कि सोने की खरीदारी से जितनी खुशी नहीं होती है उससे अधिक चिंता बढ़ जाती है। हमेशा यह चिंता सताती है कि सोना चोरी न हो जाए। इसे कैसा संभालकर रखें। पड़ोसी की नज़र सोने के गहनों पर नहीं जाए, क्योंकि नज़र लग जाएगी।यह भी कहा जाता है कि किसी अवसर पर सोने के गहने पहन लें तो हमेशा इसी पर ध्यान रहता है कि कहीं गिर न जाए, कोई खींच न ले। इस चिंता के कारण उत्सव का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाते हैं।

सोना सिर्फ आपको चिंतित ही नहीं करता है बल्कि आपकी सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इससे अभिमान भी जन्म लेता है। यही कारण है कि रहीम ने लिखा है कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। वा खाये बौराय नर, वा पाये बौराय।। इस दोहे में रहीम ने दो बार कनक शब्द का प्रयोग किया है। एक कनक धतूरे के लिए और दूसरा सोना के लिए। रहीम ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे भी ज्यादा होता है। धतूरा खाने के बाद आदमी बौरा जाता है लेकिन सोने का नशा इतना तेज होता है कि इसे प्राप्त कर लेने मात्र से इंसान बौरा जाता है। पुराणों में कथा है कि कलियुग का प्रवेश भी सोने के माध्यम से हुआ था। कलियुग सोने में निवास करता है इसलिए सोने के कारण विवाद और रिश्तों में दूरियां तक आ जाती है। साधु पुरूष कहते हैं कि सोना चिंता का बड़ा कारण है। जब आप इसे पाने की सोचने लगते हैं तभी से चिंता आपके ऊपर हावी होने लगती है।

विचार मंथन

# स्कूलों के दरवाजे बंद, सवालों से क्यों डर रहीं हैं सरकारें?

(लेखक- सनत जैन )

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों की झड़प और मारपीट की घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीजेपी का आरोप है, इस विरोध के पीछे भाजपा समर्थक थे। उपलब्ध रिपोर्ट में भाजपा ने दावा किया है, ग्रामीणों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट कर उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। मुद्दा केवल यह नहीं है, जयपुर में किसने किसे पीटा। असली प्रश्न यह है, सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखने, उसकी तस्वीर लेने और उसे जनता के सामने रखने से किसे डर लग रहा है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति अनिवार्य करने का आदेश क्यों सामने आया है? छात्रों से बातचीत करने पर क्यों रोक लगाई जा रही है? आदेश पर सरकार का तर्क बच्चों की सुरक्षा, निजता और विद्यालय में अनावश्यक व्यवधान को रोकने की बात कही जा रही है। यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब जेन-अल्फा के स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी मांग को लेकर कई राज्यों के कई स्थानों पर सड़क पर उतरे हैं। जब सीजेपी एवं अन्य राजनीतिक दल सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर अभियान चला रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और सच को छुपाने को लेकर सवाल उठते हैं।

उत्तर प्रदेश में भी बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के प्रवेश पर रोक की खबर है। वहां भी प्रशासन का तर्क सुरक्षा और पढ़ाई में व्यवधान बताया गया है। यह कहना कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें अपनी कमियां छिपाना चाहती हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, यह सवाल जरूर महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठनों की सक्रियता को इसी व्यापक राजनीति से जोड़ा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा से जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन लंबे समय से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करके वहां हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन पर इस तरीके की कोई रोक-टोक नहीं है। यदि कोई संगठन स्कूल-कॉलेजों की समसस्यों को देखकर और सुनकर समाधान के लिए प्रशासन और सरकार के सामने लाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में उसका स्वागत होना चाहिए। यही अधिकार विपक्षी दलों और स्वतंत्र सामाजिक संगठनों को भी मिलना चाहिए। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिक्षा संस्थान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं। वे जनता के पैसे से चलते हैं। वहां पढ़ने वाले बच्चे समाज के भविष्य हैं। स्कूल की टूटी छत, जर्जर भवन, शिक्षक की कमी, शौचालय, पेयजल, प्रयोगशाला या पाठ्यपुस्तकों की कमी की किसी भी समस्या को उजागर करने वाला व्यक्ति राजनीतिक विरोधी हो सकता है। कम उम्र के छात्रों की समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। ऐसी स्थिति में कम उम्र के छात्रों के अधिकार को कैसे छीना जा सकता है।

जयपुर की घटना इसलिए गंभीर है, क्योंकि सीजेपी शिक्षा एवं परीक्षा संबंधी मुहिम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। राजस्थान में प्रशासन, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं से टकराव की खबरें सामने आना चिंता का कारण है। कुछ दिन पहले अलवर में जर्जर स्कूल को लेकर सीजेपी अभियान के बाद सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट आई थी। इसका अर्थ यह है कि दबाव बनाने वाली सक्रियता से व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। राजनीति का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग मुद्दों पर नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मैदान से हटाने के लिए होने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है? तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यदि सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश किया या स्थानीय लोगों को आपत्ति थी, उसके लिए कानून के तहत शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भीड़ को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे जेन जेड और जेन अल्फा से जुड़े आंदोलनों को लेकर भी राजनीतिक दलों में नई रणनीतियां बनना शुरू कर दी हैं। छात्र एवं युवा अब आश्वासन राजनीतिक भाषण नहीं सुनता है। वह अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित समय सीमा पर चाहता है। वह सवाल का जवाब भी तुरंत चाहता है।

आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, फीस, डिजिटल अधिकार और सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता बड़े राजनीतिक मुद्दे बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा और संघ परिवार यदि युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सक्रियता बढ़ाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विपक्षी दल भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान अधिकार प्राप्त हैं। मुकाबला होना चाहिए,विचारों मे हिंसा का कोई स्थान नहीं है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## वैश्विक अस्थिरता और महंगाई चिंताओं के बीच सोना-चांदी फिर चमके

**सोना 1,205 रुपए मजबूत, चांदी में 1,745 रुपए की तेजी**

**नई दिल्ली।**

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती महंगाई की चिंताओं के बीच शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। निवेशक मुद्रा और बॉन्ड बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के कारण सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर व्यापक प्रतिबंधों की आशंका से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई की चिंताएं बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही, केंद्रीय बैंकों, विशेषकर चीन की लगातार खरीदारी ने भी बहुमूल्य धातुओं को मजबूत समर्थन प्रदान किया है। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर भी बहुमूल्य धातुओं की चमक बरकरार रही। खबर लिखे जाने के समय एमसीएक्स पर सोने का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 256 रुपये की तेजी के साथ 1,59,681 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,367 रुपये की बढ़त के साथ 2,44,610 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर था। सुबह के सत्र में सोने का बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट 1,205 रुपये की तेजी के साथ 1,60,630 रुपये पर और चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,745 रुपये की बढ़त के साथ 2,44,988 रुपये पर खुला था। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोना और चांदी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 4,592.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर था, जो पिछले बंद भाव 4,571.40 डॉलर से 21.10 डॉलर की बढ़त दर्शाता है। इसी तरह, चांदी भी 0.96 डॉलर की तेजी के साथ 69.06 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जबकि इसका पिछला बंद भाव 68.10 डॉलर था। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाएं, भू-राजनीतिक तनाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही ढीली मौद्रिक नीतियां सोने-चांदी को आगे भी समर्थन देती रहेंगी। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब पारंपरिक वित्तीय बाजार अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा अपने भंडार में सोने की खरीदारी जारी रखना भी कीमतों को उच्च स्तर पर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## महंगी चीनी से कड़वा हुआ त्योहारों का स्वाद, बंगाल में कीमतें 70 रुपए के पार

**केंद्र ने 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात की दी अनुमति; कारोबारी बोले- आयात नाकाफी**

**कोलकाता**

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सहित आगामी त्योहारी सीज़न से ठीक पहले चीनी की कीमतें आसमान छू गई हैं। खुदरा बाजार में चीनी 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जिससे उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ गया है। पिछले एक महीने में ही यह 20 रुपये महंगी हुई है। व्यापारियों के अनुसार बीते कुछ दिनों में ही कीमतों में अचानक 10 प्रतिशत का उछाल आया है। चीनी से बने गुड़, बताशा और नकुलदाना जैसे उत्पादों के दाम भी इसी तरह बढ़े हैं। कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन (सीडब्ल्यूबीटीए) के एक अे धिकारी ने चीनी मिलों पर नियंत्रण न होने और एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी के बढ़ते उपयोग को इसका मुख्य कारण बताया है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक दशक बाद 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात करने की अनुमति दी है। साथ ही, थोक खरीदारों पर भी भंडार सीमा (15 दिन की खपत) लगाई है। हालांकि, कारोबारियों का कहना है कि आयात की यह मात्रा देश की केवल दो सप्ताह की मांग को पूरा करेगी और फिलहाल इसका खुदरा बाजार पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। उनका मानना है कि अधिक हस्तक्षेप की जरूरत है। वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने चीनी की कीमत वृद्धि के लिए एथनॉल मिश्रण को नहीं बल्कि जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, एक चीनी मिल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मिलों में पेराई अप्रैल में ही खत्म हो चुकी है और अब वे केवल अपने मौजूदा भंडार से चीनी जारी कर रही हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकतीं।

# शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद

**मुंबई ।**

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की बढ़त पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच ही उतार-चढ़ा हावी रहने से बाजार पर अंकुश लगा रहा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण से भी बाजार पर दबाव आया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से भी घरेलू बाजार पर दबाव बना। दिनभर के कारोबार के बाद दोनों प्रमुख सूचकांक सपाट बंद हुए।

इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स केवल 3.11 अंक की हल्की बढ़त के साथ ही 77,540.83 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी केवल 20.15 अंक बढ़कर 24,252.00 के स्तर पर बंद हुआ। आज बड़े शेयरों में कमजोरी रही पर छोटे और मध्यम शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप सूचकांक में 0.1 फीसदी की बढ़त रही। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.69 फीसदी बढ़कर बंद हुआ।

इससे साफ है कि खुदरा निवेशकों का भरोसा छोटे शेयरों में बना हुआ है।

आज के कारोबार में धातु और निजी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा चमक रही। इन दोनों सेक्टरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया जबकि , एफएमसीजी, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा और इन्होंने बाजार के

मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया। आज सबसे अधिक गिरावट मारुति सुजुकी और इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में रही।

वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार हल्की बढ़त के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स 82.30 अंक बढ़कर 77,620.02 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी भी 18.65 अंक की बढ़त के साथ 24,250.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। ब्रॉडर मार्केट में मिलाजुला रुख दिखा।

निफ्टी मिडकैप में 0.04 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 0.44 फीसदी की अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।

## अपस्टॉक्स आईपीओ की तैयारी में, 40 करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य

**निवेश बैंकों से प्रारंभिक चर्चा शुरू, 2 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार कर कंपनी का विस्तार पर जोर**

**मुंबई ।**

प्रमुख निवेश मंच अपस्टॉक्स ने अपने महत्वाकांक्षी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए निवेश बैंकों के साथ शुरुआती चर्चा शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 35-40 करोड़ डॉलर (लगभग 3,351-3,829 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बना रही है, ऐसे समय में जब इसने अपने केवाईसी पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित आईपीओ में नए शेयर जारी करने के साथ ही मौजूदा निवेशकों की ओर से बिक्री पेशकश (ओएफएस) भी शामिल होगी। अपस्टॉक्स ने अब तक छह वित्त पोषण दौरों के माध्यम से करीब 22 करोड़ डॉलर जुटाए हैं और 2021 में 3.5 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया था। इस बीच कंपनी ने हाल ही में घोषणा की है कि उसके केवाईसी पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अपस्टॉक्स का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में अपने उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाकर 10 करोड़ तक पहुंचाना है। कंपनी के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने इस उपलब्धि पर कहा कि उनका ध्यान ग्राहकों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने और वित्तीय बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है। यह आईपीओ कंपनी को अपने विस्तार योजनाओं को गति देने में मदद करेगा।

## पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल फिर महंगा

**इस्लामाबाद ।**

पाकिस्तान की जनता को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ा है। सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद नए दाम 21 अगस्त से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 337.78 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल 364.70 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार पेट्रोल पर 114 रुपये और डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर तक का भारी टैक्स और ड्यूटी वसूल रही है, जो ईंधन की उच्च कीमतों का एक प्रमुख कारण है। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक, ये नई कीमतें 21 अगस्त से प्रभावी हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव के चलते, अब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी दैनिक आधार पर ईंधन की कीमतें तय करेगी। तुलनात्मक रूप से, भारतीय मुद्रा में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत लगभग 114.85 रुपये प्रति लीटर बैठती है, जो भारत के बड़े शहरों, जैसे दिल्ली (102.12 रुपये) और चंडीगढ़ (101.54 रुपये), की तुलना में काफी अधिक है, जिससे पाकिस्तानी उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ रहा है।

# पीएनबी की चेतावनी, निष्क्रिय खाते बंद होने का खतरा, तुरंत करें केवायसी अपडेट

**बैंक ने ग्राहकों को सितंबर तक केवायसी अपडेट करने या लेनदेन करने की चेतावनी दी**

**मुंबई ।**

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने लाखों ग्राहकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। बैंक ने ऐसे निष्क्रिय खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है जिनमें लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है और जिनका बैलेंस शून्य है। ग्राहकों को सितंबर तक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, ताकि उनके खाते बंद होने से बच सकें। पीएनबी के अनुसार, ऐसे बैंक खाते जिनमें पिछले तीन साल से कोई लेनदेन दर्ज नहीं हुआ है और खाते में कोई राशि भी नहीं है, उन्हें बंद किया जा सकता है। बैंक ने यह कदम खातों के गलत इस्तेमाल और उनसे जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए उठाया है। पीएनबी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों पर भी यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें खाताधारकों को सचेत किया गया है। निष्क्रिय खाताधारक अपने खाते को बंद होने से बचाने के लिए सितंबर तक संबंधित बैंक शाखा में अपने केवायसी दस्तावेज जमा कराकर इसे दोबारा सक्रिय करवा सकते हैं। केवायसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राहक बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे।

बैंक ने यह भी सलाह दी है कि कोई भी ग्राहक अपना खाता बंद करने का निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह पेंशन, सब्सिडी, लोन, बीमा या किसी अन्य महत्वपूर्ण भुगतान से जुड़ा न हो। पीएनबी ने ग्राहकों से समय-समय पर अपने खाते में लेनदेन करने और अपनी केवायसी जानकारी अपडेट रखने का आग्रह किया है।

किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए ग्राहक पीएनबी के आधिकारिक हेल्पलाइन माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।

# भारतीय प्राइवेट क्रेडिट बाजार गुलजार, रियल एस्टेट सबसे आगे

**अगले 1-2 वर्षों में बाजार की मजबूती बरकरार रहने का अनुमान**

**नई दिल्ली ।**

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्राइवेट क्रेडिट बाजार अगले एक से दो वर्षों में भी मजबूत बना रह सकता है। एच1 2026 में रियल एस्टेट सेक्टर ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जबकि घरेलू निवेशकों ने वैश्विक फंड्स को पीछे छोड़ दिया। इस अवधि में करीब 3.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ। एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2026 की पहली छमाही (एच1 2026) में भारत के प्राइवेट क्रेडिट बाजार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू आर्थिक आधार और बेहतर बैंकिंग सेक्टर से प्रेरित था। इस दौरान कुल निवेश लगभग 3.5 अरब डॉलर रहा, जिसमें घरेलू फंड्स का दबदबा रहा। कुल डील वैल्यू में घरेलू खिलाड़ियों की हिस्सेदारी 74 फीसदी रही, जबकि डील की संख्या में यह आंकड़ा 79 फीसदी रहा। सेक्टरवार विश्लेषण में रियल एस्टेट कुल प्राइवेट क्रेडिट डील वैल्यू के 35 फीसदी हिस्से के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद हेल्थकेयर (13 फीसदी) का स्थान रहा। एक महत्वपूर्ण बदलाव फूड एंड बेवरेज (एफएंडबी) सेक्टर में देखा गया, जिसकी हिस्सेदारी एच 2 2025 में मात्र 1 फीसदी से बढ़कर एच1 2026 में 12 फीसदी पर पहुंच गई। यह तेजी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति से भी प्रेरित है। मार्च 2026 तक बैंकों का कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो 17.7 फीसदी और सीईटी1 अनुपात 15.3 फीसदी रहा। वित्तीय वर्ष 2026 में सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.8 फीसदी और शुद्ध एनपीए 0.4 फीसदी रह गया, जो एसेट क्वालिटी में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। सर्वे में शामिल 60 फीसदी प्रतिभागियों ने अगले 1-2 वर्षों के लिए भारतीय प्राइवेट क्रेडिट बाजार को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा एक चिंता का विषय बनी हुई है। रियल एस्टेट, हालांकि सबसे सक्रिय सेक्टर है, इसे डिफॉल्ट के लिहाज से सबसे जोखिम भरा भी माना गया है। स्ट्रेस, कैपेक्स और विलय-अधिग्रहण फाइनेंसिंग इस बाजार की प्रमुख मांग बने हुए हैं।

## रुपया बढ़त के साथ बंद

**मुंबई ।**

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 5 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.69 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में रुपया नौ पैसे बढ़क 95.65 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की चुनौती से भारत के लिए कमजोर डॉलर का असर कम हो रहा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.69 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में 95.65 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से नौ पैसे की बढ़त है। वहीं रुपया गुरुवार को शुरुआती बढ़त गंवाकर एक पैसे की गिरावट के साथ 95.74 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.15 फीसदी टूटकर 98.74 पर आ गया।

## टाटा मोटर्स की गाड़ियां होंगी महंगी, 1 सितंबर से 25,000 तक बढ़ेंगे दाम

**कच्चे माल की बढ़ती लागत और वैश्विक चुनौतियों के कारण कंपनी ने लिया फैसला**

**नई दिल्ली ।**

अगर आप टाटा मोटर्स की कोई नई कार या एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। कंपनी ने अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 1 सितंबर 2024 से 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यह कदम कच्चे माल की लगातार बढ़ती लागत और वैश्विक बाजार में बनी अनिश्चितता के चलते उठाया गया है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह मूल्य वृद्धि उसके पूरे यात्री वाहन पोर्टफोलियो पर लागू होगी। हालांकि, किस मॉडल और वैरिएंट की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका खुलासा कंपनी ने नहीं किया है। अधिकतम बढ़ोतरी 25,000 रुपये तक होगी। कंपनी ने बताया कि कच्चे माल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के कारण भी कंपनियों के खर्च पर भारी दबाव बना हुआ है। कंपनी अब तक बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही थी, लेकिन लगातार बढ़ते खर्चों के कारण अब इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना अनिवार्य हो गया है। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में रुकावट, महंगा कच्चा माल और बढ़ती परिचालन लागत वाहन कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भी ऊर्जा और आपूर्ति से जुड़ी लागतों पर पड़ रहा है। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन पोर्टफोलियो में टियागो, टिगोर, पंच, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर और सफारी जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे खरीदारी से पहले अपने नजदीकी डीलर से नई कीमतों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। यह 2024 में टाटा मोटर्स की ओर से की जाने वाली तीसरी मूल्य वृद्धि होगी। इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल से पेट्रोल-डीजल वाले यात्री वाहनों की कीमतों में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 1 जुलाई से कंपनी ने अपने पूरे यात्री वाहन पोर्टफोलियो के दाम 1.5 फीसदी बढ़ाए थे। अब 1 सितंबर से एक बार फिर कीमतों में 25,000 रुपये तक की वृद्धि होने जा रही है, जो ग्राहकों के लिए चुनौती पेश कर सकती है।

## सेबी की बड़ी कार्रवाई, दो कंपनियों पर लगा प्रतिबंध

**गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे जब्त करने का निर्देश**

**मुंबई**

बाजार नियामक सेबी ने सेंसेक्स डेरिवेटिव्स अनुबंधों की साप्ताहिक अंतिम तिथि पर हुई कीमतों की असामान्य हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। एक विस्तृत जांच के बाद, सेबी ने जेपी मॉर्गन की मॉरीशस स्थित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) कॉपटॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग को बाजार में कीमतों की कृत्रिम छेड़छाड़ का दोषी पाया है। नियामक ने इन कंपनियों को शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है और उनसे गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को जब्त करने का आदेश दिया है। यह मामला 13 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान सेंसेक्स में कुछ ही सेकंड में हुई कीमतों की अचानक उछाल से जुड़ा है। सेबी की अंतरिम जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस उछाल के पीछे कॉपटॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट का हाथ था। कंपनी ने लगभग 98 रुपए करोड़ मूल्य के खरीद ऑर्डर दिए, जिनकी कीमत संदर्भ मूल्य से अधिकतम 3 फीसदी अधिक थी और कीमतों में बदलाव के साथ ही एक-तिहाई ऑर्डर रद्द कर दिए। सेबी का आरोप है कि कॉपटॉल ने सेंसेक्स के सांकेतिक समान मूल्य (आईईपी) को बढ़ाकर बंद भाव में हेरफेर करने की कोशिश की, ताकि अपनी सिंथेटिक लॉन्ग एसेट पोजीशन से मुनाफा कमाया जा सके।

उसी दिन, मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग ने सेंसेक्स की आठ कंपनियों के शेयरों में संदर्भ मूल्य से लगभग 2.5 फीसदी कम पर बड़ी संख्या में बिक्री ऑर्डर दिए, जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया। इससे सेंसेक्स का आईईपी चार से पांच मिनट तक नीचे आ गया, जिससे कंपनी को वायदा पोजीशन से लाभ मिलने की संभावना थी। नियामक ने स्पष्ट किया है कि दोनों संस्थाओं ने आपस में मिलकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से हेरफेर किया। सेबी के चेयरमैन ने बाजार में हेरफेर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन घटनाओं ने बाजार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ाई है और वे सीएएस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

## बंगाल का औद्योगिक सपना, दशकों का सफर और अनसुलझी तस्वीर

**कोलकाता की चमकीली शहरी छवि, औद्योगिक मोर्चे पर स्थायी बदलाव की चुनौती**

**नई दिल्ली ।**

पश्चिम बंगाल ने पिछले तीन दशकों में अपनी औद्योगिक और आर्थिक छवि को बदलने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। 1994 में वाम मोर्चा सरकार द्वारा निजी निवेश के द्वार खोलने से लेकर आज तृणमूल कांग्रेस के आईटी हब के प्रयासों तक, राज्य ने निवेश आकर्षित करने और अपनी उग्र मजदूर संघों वाली छवि से उबरने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि, चमकदार शहरी विकास के बावजूद, राज्य की औद्योगिक तस्वीर अभी भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। सितंबर 1994 में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नेतृत्व में, निजी निवेश के लिए द्वार खोलते हुए एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। लाइसेंस राज के ढहने के बाद, राज्य ने चुनिंदा क्षेत्रों में नई तकनीक और निवेश का स्वागत किया। हालांकि, अप्रैल 2000 में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन अनेक समझौता ज्ञापन (एमओयू) ठोस निवेश या रोजगार में तब्दील नहीं हो पाए। तब तक राज्य की पहचान उग्र मजदूर संघों और औद्योगिक अशांति वाले प्रदेश के रूप में स्थापित हो चुकी थी, जिससे निवेशक दूर भाग रहे थे। नवंबर 2000 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। उनके अभी करो वाले दृष्टिकोण ने औद्योगीकरण को गति दी। कोलकाता में साल्ट लेक और राजारहाट जैसे क्षेत्रों में आईटी कंपनियों के परिसर, भव्य शॉपिंग मॉल और रेस्तरां तेजी से विकसित हुए। इन आधुनिक केंद्रों ने शहर के पुराने औपनिवेशिक स्वरूप से हटकर एक नई व्यावसायिक पहचान गढ़ी, जो कांच और इस्पात के टावरों से चमक उठी। पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में भी यह गति जारी रही, जिसमें बंगाल सिलिकॉन वैली टेक हब जैसी परियोजनाओं ने आईटी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इनमें से अधिकांश परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं। नए दफ्तरों और फ्लाईओवर ने भले ही कोलकाता की भौतिक तस्वीर बदल दी हो, लेकिन राज्य की औद्योगिक छवि में आया बदलाव अस्थायी प्रतीत होता है।

# निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों में मामूली सुधार, सर्विस सेक्टर ने संभाली कमान

**अगस्त में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 54.6 हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई सुस्ती**

**नई दिल्ली ।**

भारत के निजी क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियों में अगस्त में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। जुलाई में चार साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद यह सुधार सेवा क्षेत्र की मजबूत रफ्तार से संभव हुआ, जिसने विनिर्माण क्षेत्र की धीमी पड़ती गतिविधियों को काफी हद तक संतुलित किया। एक सर्वे के मुताबिक अगस्त में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 54.6 पर पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 54.3 था। जारी सर्वे के अनुसार अगस्त में निजी क्षेत्र की गतिविधियों में विस्तार लगातार 61वें महीने बना रहा, हालांकि कंपोजिट पीएमआई मार्च 2022 के बाद दूसरा सबसे कमजोर आंकड़ा रहा। इस दौरान सेवा क्षेत्र की कारोबारी गतिविधियां जुलाई के 53.3 से बढ़कर 54.5 हो गईं, जो वृद्धि को प्रमुख सहारा मिला। इसके विपरीत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ और धीमी पड़ गई। पीएमआई जुलाई के 53.5 से घटकर अगस्त में 52.9 रह गया। एक अर्थशास्त्री ने बताया कि विनिर्माण ग्रोथ पांच साल में सबसे धीमी रही। नए ऑर्डर में सुधार हुआ, लेकिन उसकी गति उम्मीद से कम रही।

कंपनियों की इनपुट लागत सात महीनों की सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी, फिर भी उन्होंने ग्राहकों से वसूले जाने वाले अंतिम बिक्री मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी की। अगस्त में कुल रोजगार सृजन में सुधार हुआ, जिसका मुख्य कारण सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की भर्ती थी। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ढाई साल में पहली बार कर्मचारियों की संख्या में कमी दर्ज की गई। कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े जुलाई की तुलना में कुछ राहत देते हैं, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की लगातार कमजोर होती ग्रोथ और समग्र पीएमआई का अपेक्षाकृत निचला स्तर आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार पर दबाव बने रहने का संकेत देता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## श्रीलंका ने कोलंबो टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम का किया ऐलान

**नई दिल्ली, एजेंसी।** श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने भारत के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है। 14 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर सहन अराचिगे और बल्लेबाज कामिल मिशारा को शामिल किया गया है। पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए दिनेश चांदीमल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट रहे पासिंदु सोरियाबंदारा को भी टीम से बाहर रखा गया है। दूसरे ओपनर निशान मदुश्का को जगह नहीं मिली, जबकि गेंदबाजी ऑलराउंडर रमेश मेंडिस और तेज गेंदबाज दिलशान मदुश्का भी टीम में जगह नहीं बना सके। अराचिगे को भारत ए के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। अराचिगे ने भारत ए के खिलाफ हाल ही में श्रीलंका ए क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अराचिगे ने पहले मैच में 72 और दूसरे मैच में 127 रन की पारी खेली थी। दो अनाधिकारिक मैचों की सीरीज में भारतीय साई सुदर्शन के बाद अराचिगे दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे थे। अराचिगे को टेस्ट डेब्यू का इंतजार है। मिशारा लंका प्रीमियर लीग 2026 में शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने हाल के सीजन में नौ पारियों में 411 रन बनाए थे। उन्होंने गॉल गैलेंट्स के खिलाफ शतक भी बनाया था। वे मेजर क्लब्स टी20 कॉम्पिटिशन में शानदार फॉर्म में थे और महज 72 गेंदों पर 145 रन की पारी खेली थी। श्रीलंका पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। सीरीज बचाने के लिए श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। पहला टेस्ट टीम इंडिया ने 165 रन से जीता था।

**श्रीलंका टीमः**

लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, पासिंदू सोरियाबंदारा, कामिंडू मेंडिस (उपकप्तान), धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सहन अराचिगे, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो।

## कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने टीम इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी की

**कोलंबो, एजेंसी।** श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंडिया हाउस में भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की। भारतीय उच्चायुक्त झा ने गुरुवार रात भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही श्रीलंकाई टीम की भी मेजबानी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी दी है और इसे एक 'यादगार शाम' बताया है। बीसीसीआई ने अपने एक्स में लिखा, 'कोलंबो में एक यादगार शाम। श्रीलंका में इंडिया के उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले कोलंबो के इंडिया हाउस में भारतीय टीम की मेजबानी की।' झा ने दोनों टीमों की मेजबानी करके खुशी जाहिर की और कार्यक्रम की कुछ झलकियां एक्स पर साझा की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टीम इंडिया के साथ चीयर कर रहा हूं। श्रीलंका में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचों के दौरान भारतीय और श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीमों की मेजबानी करके खुशी हो रही है। खेल के लिए एक जैसे जुनून से बंधा, क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा रहने वाले रिश्तों को और मजबूत कर रहा है।' भारत ने गाले में पहले टेस्ट में 165 रन की बड़ी जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। गाले टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बनाए थे। श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटकर 178 रनों से पिछड़ी थी। भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रन पर सिमटी और पहली पारी में मिले 178 रन की बढ़त के आधार पर श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका दूसरी पारी में 206 रन पर सिमट गई और 165 रन से मैच हार गई। दूसरी पारी में भारत के लिए मानव सुथार ने 6 विकेट लिए थे।

**सिनसिनाटी ओपन**

# इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंची

**सिनसिनाटी, एजेंसी।** एलेना रयबाकिना को सिनसिनाटी ओपन क्वार्टर फाइनल मैच से बाएं टखने में चोट के कारण बाहर होना पड़ा। इंजरी की वजह से जहां वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं, वहीं उनकी विपक्षी इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंच गईं। मैच के दौरान स्वियाटेक 4-1 से आगे थीं और रयबाकिना 40-15 पर सर्व कर रही थीं। उसी समय रयबाकिना के लिए मुश्किल शुरू हुई। रयबाकिना नेट पर एक रैली खत्म नहीं कर सकीं। डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के अनुसार, अगले पॉइंट पर उन्हें अपनी पहली सर्व पर पुश करने में मुश्किल हुई, जो सिर्फ तीन शॉट तक चली, और गेम के बीच में मेडिकल जांच के बाद, रयबाकिना ने कुछ देर बाद मैच खत्म करने का फैसला किया। रायबाकिना ने कहा, 'मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सर्व से पुश भी नहीं कर पा रही थी। चलने में दर्द हो रहा है। एमआरआई के बाद समस्या के बारे में और पता चलेगा।' उन्होंने कहा, 'यह मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। कनाडा में बहुत सारे मैच खेलने और यहां लगातार दो मैच खेलने के बाद और मैच से पहले ठीक लग रहा था लेकिन बदकिस्मती से एक गलत मूवमेंट, एक लैंडिंग, और समस्या शुरू हो गई।' बुधवार को चौथे राउंड में सारा बेजलेक

**एलेना रयबाकिना इंजरी की वजह से बाहर**

**सिनसिनाटी ओपन**

## आर्थर फिल्स ने थियागो अगस्टिन टिरेंटे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

**सिनसिनाटी, एजेंसी।** आर्थर फिल्स ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फिल्स ने 64 मिनट तक चले मुकाबले में थियागो अगस्टिन टिरेंटे को 6-3, 6-2 से हराया। फिल्स ने इस सीजन के तीसरे एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 22 साल के फिल्स एक सीजन में तीन मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी बन गए। उनसे पहले गाइ फॉरगेट ने 1991 में यह उपलब्धि हासिल की थी। फरवरी में आठ महीने की चोट के बाद वापसी करते हुए फिल्स का शानदार सीजन रहा है। एटीपी जीत/हार इंडेक्स के मुताबिक, इस साल फ्रेंचमैन का टूर-लेवल रिकॉर्ड 30-10 रहा है, जिसमें बार्सिलोना में एक खिताब और मियामी और मैड्रिड में मास्टर्स 1000 इवेंट्स के सेमीफाइनल में पहुंचना शामिल है।

पहले सेट में 4-3 पर एक अहम ब्रेक हासिल करने के बाद, फिल्स ने लगातार जबरदस्त फोरहैंड लगाए, जिससे टिरांटे लगातार बैकफुट पर रहे। एटीपी के मुताबिक, 22 साल के खिलाड़ी ने दूसरे सेट में अर्जेंटीना के खिलाड़ी की सर्विस दो बार तोड़ी और पूरे मैच के दौरान उन्हें कभी भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। अब वह टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए फ्लेवियो कोबोली से भिड़ेंगे, दोनों खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचना चाहते हैं।

कोबोली ने घरेलू पसंदीदा टॉमी पॉल के खिलाफ 2-6, 6-3, 6-4 से जीत हासिल की और ओहियो में अपने पहले मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गए। 24 साल के खिलाड़ी अब जून में रोलैंड गैरोस चैंपियनशिप मैच में पहुंचने के बाद अपने पहले सेमीफाइनल की तैयारी करेंगे। वह 2024 और 2025 में जैनिक सिनर के बाद सिनसिनाटी में अंतिम चार में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे इटैलियन खिलाड़ी हैं। पॉल के खिलाफ जीत के साथ, कोबोली ने यह भी पक्का कर लिया कि वह सोमवार को एटीपी रैंकिंग में अपने करियर की नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वह अभी लाइव रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 6 पर हैं।

## जैकब मार्टिन को 22 साल पुराने में पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत दी है। 2004 के इस मामले में कोर्ट ने मार्टिन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर पर फर्जी यूके आव्रजन स्टाम्प, यात्रा व्यवस्था और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा आरोप लगाया गया था, जिसे साबित नहीं किया जा सका। अदालत को वित्तीय लेनदेन या अजवा स्पोर्ट्स क्लब पर उनके स्वामित्व या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। कई गवाह भी इन आरोपों को साबित करने में विफल रहे। मीडिया से बात करते हुए मार्टिन ने बताया कि यह मामला 2004 में उनकी टीम के एक सदस्य द्वारा ब्रिटेन का वीजा समाप्त होने के बाद वहां रुकने और फर्जी आव्रजन स्टाम्प लगवाकर भारत लौटने के बाद शुरू हुआ था। मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था। बाद में उनका नाम मामले में जोड़ दिया गया। घटना के बारे में मार्टिन ने कहा, 2004 में टीम इंग्लैंड खेलने गई थी। जो टीम 2004 में इंग्लैंड गई थी, उसमें से एक लड़के को छोड़कर बाकी सब वापस आ गए। वीजा की वैधता छह महीने की थी, वह छह महीने तक रह सकता था। वह इससे अधिक समय तक रुका रहा। किसी के जरिए उसने वहां फर्जी स्टैंपिंग करवा ली। फर्जी स्टैंपिंग कराने के बाद जब वह भारत वापस आया, तो उसे ब्रिटेन से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और फिर उससे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा, 'मेरा नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जब जांच हुई, तो एक बड़ा नाम होने के नाते मुझे इस मामले में घसीटा गया।

## यूएस ओपन 2026: प्राइज मनी में भारी वृद्धि

**नई दिल्ली, एजेंसी।** ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा प्राइज मनी बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों की ये मांग पूरी होने वाली है। यूएस ओपन में इस बार खिलाड़ियों के प्राइज मनी में इजाफा होने वाला है। यूएस ओपन की प्राइज मनी में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। खिलाड़ियों की कुल सैलरी बढ़कर 108 मिलियन डॉलर हो गई है। टूर्नामेंट से पहले, यूएसटीए (यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन) ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की। यूएसटीए के सीईओ क्रेग टिली ने कहा कि यह कदम खेल के आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है। यह एथलीटों में कई सालों के निवेश में एक अहम पहला कदम है क्योंकि यूएस ओपन खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा आर्थिक मौका और खिलाड़ियों, फैंस और पार्टनर्स के लिए टेनिस में सबसे कीमती प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एकल विजेता को 52.65 करोड़ मिलेंगे। वहीं, एकल फाइनल में हारने वाले खिलाड़ी को करीब 26.80 करोड़ रुपये (2.8 मिलियन) दिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को लगभग 7.46 करोड़ रुपये (780,000) और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले प्लेयर्स को करीब 13.88 करोड़ रुपये (1.45 मिलियन) मिलेंगे। डबल्स मुकाबलों में पुरुष, महिला और मिक्स जीतने वाले प्लेयर्स को लगभग 9.57 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिन्हें वे आपस में बाटेंगी। वहीं उपविजेता टीमों को करीब 5,00,000 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। इसके अलावा, व्हीलचेयर सिंगल्स के चैंपियन्स को लगभग 99 लाख रुपये (1,04,000) की इनामी राशि मिलेगी। पहले ही मैच में हारकर बाहर होने वाले खिलाड़ी को भी लगभग भारतीय रुपये में 1.34 करोड़ रुपये (140,000) मिलेंगे। यूएस ओपन रोमांचक होने वाला है। पिछले 4 महीने से पेशेवर टेनिस से दूर रहे पूर्व चैंपियन कार्लोस अल्काराज अपना खिताब बचाने के लिए उतरेंगे। अल्काराज ने अप्रैल के बाद से एक भी मैच नहीं खेला है। उन्हें बार्सिलोना ओपन के दौरान कलाई में चोट लग गई थी। चोट की वजह से वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और कई दूसरे टूर्नामेंट से भी बाहर रहे। यूएस ओपन 2026 की शुरुआत 23 अगस्त से होगी और 13 सितंबर को पुरुषों के फाइनल के साथ खत्म होगा।

## डोपिंग को लेकर नाडा की बड़ी कार्रवाई, इस भारतीय भाला फेंक एथलीट पर लगाया 10 साल का प्रतिबंध

**नई दिल्ली, एजेंसी।** राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने डोपिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। ओलंपियन भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्व एशियाई रजत पदक विजेता और ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासनात्मक पैनल ने 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। शिवपाल प्रतिबंधित पदार्थ मेथाएंडिएनोन के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। 31 साल की उम्र में यह प्रतिबंध उनके खेल करियर का अंत कर सकता है। शिवपाल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

### पहले लगा था चार साल का प्रतिबंध

नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने अगस्त 2022 में उन्हें डोपिंग उल्लघंन का दोषी मानते हुए 2021 से चार साल का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 2025 तक चलना था, लेकिन शिवपाल ने नाडा के अपील पैनल के सामने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि उनकी डोप जांच में पॉजिटिव आने के पीछे दूषित सप्लीमेंट्स जिम्मेदार थे। जनवरी 2023 में अपील पैनल ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए प्रतिबंध को चार साल से घटाकर सिर्फ एक साल कर दिया।

### एशियाई चैंपियनशिप में जीता था रजत

शिवपाल के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतना है। दोहा में उन्होंने 86.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह पदक हासिल किया था। हालिया मामलों में कार्रवाई का सामना करने वाले शिवपाल अकेले भारतीय एथलीट नहीं हैं। धाविका एमवी जिल्ना को भी दूसरे डोपिंग उल्लघंन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया और वह मेफेंटरमाइन के लिए पॉजिटिव मिलीं। इससे पहले 2021 में शिवपाल का डोप नमूना प्रतियोगिता से बाहर की गई जांच में एक स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव आया था।

## कट शॉट बना यशस्वी जायसवाल का 'दुश्मन', 27 गेंदों में 4 बार फंसे...कोलंबो टेस्ट से पहले की गंभीर तैयारी

**नईदिल्ली, एजेंसी।** भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के एसएससी मैदान में 23 अगस्त (रविवार) से होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले यशस्वी जायसवाल अपनी एक खास कमजोरी पर जोरदार मेहनत कर रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है. मुकाबले से दो दिन पहले यशस्वी जायसवाल ने नेट्स में अपनी उस कमजोरी पर खास तौर पर काम किया, जो गॉल टेस्ट में फिर सामने आई थी. ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंदबाजों की गेंद पर कट शॉट खेलने की उनकी आदत इन दिनों परेशानी बनती दिख रही है. भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल अब तक 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन्होंने हर टेस्ट अलग-अलग मैदान पर खेला है. टेस्ट डेब्यू से लेकर अब तक उनका सफर कैरेबियाई देशों, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और अब श्रीलंका तक पहुंच चुका है. सिर्फ तीन साल के टेस्ट करियर में ही जायसवाल भारतीय बल्लेबाजी की अहम कड़ी बन चुके हैं. सफेद गेंद क्रिकेट वाली उनकी आक्रामकता

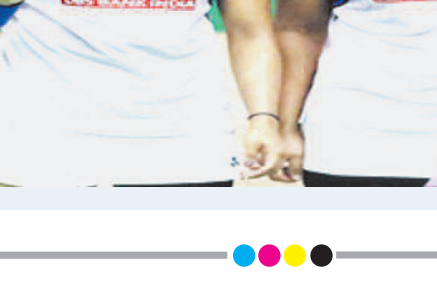

### नेट्स में शुरू हुआ सुधार का काम

जायसवाल के गलत शॉट खेलने का प्रतिशत भी बढ़ा है. पहले यह आंकड़ा 31.1 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 48.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यही वजह रही कि शुक्रवार को कोलंबो के स्पष्ट मैदान पर भारत के तेज गेंदबाजों ने नेट्स में उन्हें लगातार इस एरिया में परखने की कोशिश की.

### कट शॉट बना परेशानी की वजह?

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के तेज गेंदबाज फर्नांडो ने जायसवाल को ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद पर फंसाया. जायसवाल गेंद को कट करने के लिए गए, लेकिन किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर डिकवाला के पास चली गई. आंकड़े बताते हैं कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलते हुए आउट होने का पैटर्न हाल के महीनों में बढ़ा है. पिछले साल अक्टूबर में भारतीय घरेलू टेस्ट सीजन शुरू होने के बाद से जायसवाल सिर्फ 27 गेंदों में तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलने के प्रयास में चार बार आउट हो चुके हैं. वहीं टेस्ट डेब्यू से लेकर पिछले साल इंग्लैंड दौरे तक, करीब दो साल के दौरान वह 190 गेंदों में सिर्फ चार बार इस शॉट पर आउट हुए थे. यानी हाल के समय में यह कमजोरी ज्यादा साफ होकर सामने आई है.

**बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप**

# त्रिसा-गायत्री ने दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी को हराया, महिला डबल्स में मेडल पक्का

**नई दिल्ली, एजेंसी।** भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी जी यिफान और झांग शुक्सियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। त्रिसा-गायत्री की जीत ने देश के लिए मेडल पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने एक गेम पीछे रहने के बाद चीनी जोड़ी पर 16-21, 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की और महिला डबल्स में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली दूसरी जोड़ी बन गई। इससे पहले महिला डबल्स में 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने कांस्य पदक जीता था। शुरुआत में भारतीय जोड़ी कमजोर दिखी क्योंकि जिया और झांग ने 6-2 की बढ़त बना ली और शुरुआती गेम तक अपनी बढ़त बनाए रखी। त्रिसा और गायत्री ने धीरे-धीरे अपनी आक्रामक रिदम पाई, अपने पावरफुल स्मैश और नेट के दम पर अंतर को 8-9 कर दिया। हालांकि, रिकवरी इतनी नहीं थी कि चीनी खिलाड़ी को 11-8 की बढ़त के साथ ब्रेक में जाने से रोका जा सके और आखिरकार शुरुआती गेम 21-16 से जीत लिया। दूसरे गेम भारतीयों ने अपने विरोधियों को वैसा नियंत्रण नहीं करने दिया, लंबी रैलियों में उनका मुकाबला किया और दबाव में डिफेंड करते हुए इंटरवल पर 11-10 की मामूली बढ़त हासिल की। वहां से, त्रिसा और गायत्री और ज्यादा आक्रामक हो गईं। उनके क्रॉस-कोर्ट अटैक ने बार-बार चीनी जोड़ी को कोर्ट के पार खींचा, जबकि उनके डिफेंस ने जिया और झांग के दबाव को झेला। इंडियन्स ने 17-14 की बढ़त के साथ शुरुआत की और फिर गेम 21-15 से खत्म करके निर्णायक बना दिया। निर्णायक गेम में 4-4 से बराबरी की शुरुआत के बाद, त्रिसा ने एक जोरदार स्मैश से ब्रेकथ्रू पाया, और भारतीय जोड़ी ने बढ़त बना ली। लगातार सात पॉइंट्स ने मैच का पासा पलट दिया, जिससे वे 4-4 से 9-4 पर आ गए। त्रिसा के अटैक ने चीनी जोड़ी को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। भारतीय जोड़ी ने 11-5 की बड़ी बढ़त के साथ इंटरवल में एंट्री की। साइड बदलने के बाद, जिया और झांग ने थोड़ी देर के लिए अपनी चुनौती को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने लगातार तीन पॉइंट्स जीतकर अपनी लय वापस पा ली। चीनी जोड़ी पर बढ़ते दबाव के साथ, उनके गेम में गलतियां होने लगीं। 18-9 पर, भारतीय बस बराबरी पर थे। झांग के शॉट को आउट दिए जाने के बाद एक समीक्षा से नतीजे में ज्यादा बदलाव नहीं आया। चीनी जोड़ी की दो और गलतियों ने त्रिसा और गायत्री को निर्णायक पाइंट दिला दिए। इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी का पदक पक्का हो गया।

## संक्षिप्त समाचार

### प्रिंस हैरी शाही भूमिकाओं के बिना ब्रिटेन लौटेंगे; भारतीय महिला को इस्राइल में अच्छी नागरिकता सम्मान

**लंदन, एजेंसी।** ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन ने यूनाइटेड किंगडम लौटने का फैसला किया है। हालांकि, वे शाही परिवार के कामकाजी सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाएं फिर से शुरू नहीं करेंगे। किंग चार्ल्स को रविवार को इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया। हालांकि, पिछले महीने दंपती की यूके यात्रा के दौरान उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया था। डेली टेलीग्राफ ने यह खबर सबसे पहले प्रकाशित की है। अखबार के अनुसार, हैरी और मेघन के बच्चे, प्रिंस आर्ची (7) और प्रिंसेस लिलिबेट (5), ब्रिटिश स्कूलों में पहले ही दाखिला ले चुके हैं। वे सितंबर में अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे। यह निर्णय दंपती द्वारा अपनी शाही जिम्मेदारियां छोड़ने के छह साल से अधिक समय बाद आया है। उन्होंने आकर्षक मीडिया अनुबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया का रुख किया था। ब्रिटेन लौटने से किंग चार्ल्स को अपने पोते-पोतियों से अधिक मिलने का अवसर मिलेगा। किंग चार्ल्स एक अज्ञात प्रकार के कैंसर का इलाज करा रहे हैं। दंपती ने छह साल से अधिक समय पहले अपने शाही कर्तव्यों को त्याग दिया था। वे कैलिफोर्निया में बस गए थे। इस वापसी से परिवार के संबंधों में मजबूती आ सकती है।

### इस्राइल में देखभाल करने वाली भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता का सम्मान

**यरुशलम, एजेंसी।** इस्राइल पुलिस ने एक भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है। देखभाल करने वाली इस महिला ने कार्मेल क्षेत्र में 95 वर्षीय होलोकॉस्ट पीड़ित को ठगी के प्रयास से बचाया था। बुधवार को तटीय जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में हाइफा पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने हीरा (हीराबेन) को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हीराबेन उस बुजुर्ग महिला की नर्सिंग देखभालकर्ता यानी केयरगिवर के रूप में काम कर रही हैं। इजरायल में कुछ ही महीने रहने के बावजूद, हीराबेन ने सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उन्होंने महिला को एक कथित धोखेबाज से बचाया, जो क्लैलिट हेल्थ सर्विसेज की नर्स बनकर उनके अपार्टमेंट में आया था। देखभालकर्ता ने शांत रहते हुए घटना को दर्ज किया, संदिग्ध को बुजुर्ग महिला के पास जाने से रोका और पुलिस को सूचित किया। इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और संदिग्ध की हिरासत दो दिन पहले कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक बढ़ा दी गई थी। जांचकर्ता नोफर पाज़ ने बुजुर्ग महिला और उनके परिवार की उपस्थिति में हीराबेन को धन्यवाद दिया।

### सफारी के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, पांच अमेरिकी समेत सात लोगों की मौत

**नैरोबी, एजेंसी।** केन्या के उत्तरी हिस्से में बुधवार सुबह सफारी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक शामिल थे। हेलीकॉप्टर सुबह 9ः13 बजे लॉइसाबा कंजरवेंसी से साम्बुरु काउंटी के इवासो न्यिरो इलाके की ओर जा रहा था। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हेलीकॉप्टर में कुल सात लोग सवार थे। इनमें छह यात्री और एक पायलट था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। साम्बुरु के पुलिस कमांडर डेविड नकोरोई ने बुधवार देर शाम पुष्टि की कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और पीड़ितों से जुड़े लोगों को जरूरी कांसुलर सहायता उपलब्ध करा रहा है। मृतकों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक स्थानीय टीवी स्टेशन ने बताया कि मृतकों में जोस सुआरेज भी शामिल थे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी और वह टेलीमुंडो के फ्लोरिडा स्थित कई स्टेशनों के अध्यक्ष और महाप्रबंधक थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर माउंट ओलोलोक्के की तलहटी में स्थित एक दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाके में गिरा। यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हेलीकॉप्टर स्थानीय कंपनी लेडी लॉरी हेलीकॉप्टर्स का था और चार्टर उड़ान के तहत यात्रियों को ले जा रहा था। सफारी कंपनी एंडबियॉन्ड के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए यह उड़ान संचालित की गई थी। ट्रॉपिक एयर केन्या ने तलाश और बचाव अभियान में मदद के लिए अपने दो हेलीकॉप्टर भेजे। केन्या रेड क्रॉस की आपातकालीन टीमें भी बहु-एजेंसी राहत अभियान में शामिल हुईं।

## गंगा जल पर फिर तनातनी: गारंटी प्रावधान मांगने की तैयारी में बांग्लादेश, क्या भारत से बिगड़ेंगे रिश्ते

**ढाका, एजेंसी।** बांग्लादेश ने भारत के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पड़ोसी मुल्क अब नई संधि में 'गारंटी प्रावधान' शामिल करने की मांग करेगा। साथ ही उसने संकेत दिया है कि पानी के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख भी किया जा सकता है। जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने मंगलवार को ढाका में आयोजित एक संगोष्ठी में यह बात कही। संगोष्ठी का विषय था- 'गंगा जल संधिः पुनर्विचार के मुद्दे'। इसका आयोजन बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने किया था। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने इसकी जानकारी दी।

**दिसंबर में समाप्त होने वाली है गंगा जल संधि :** भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि दिसंबर में समाप्त होने वाली है। यह संधि सूखे मौसम में गंगा के पानी के बंटवारे की व्यवस्था करती है। अनी ने कहा कि बांग्लादेश संधि पर दोबारा बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश का पक्ष मजबूती से रखेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को संधि चाहिए। उनके मुताबिक, बिना संधि के आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है और यह बांग्लादेश का अधिकार है।

**क्या 1977 वाला गारंटी प्रावधान फिर लौटेगा :** अनी ने



भविष्य की जल-बंटवारा संधियों में सूचना के अधिकार से जुड़ा प्रावधान शामिल करने की जरूरत बताई। उन्होंने 1977 की गंगा संधि में मौजूद 'गारंटी प्रावधान' को फिर शामिल करने की मांग की। यह प्रावधान 1996 की संधि में नहीं रखा गया था। गारंटी प्रावधान का मतलब है कि निचले हिस्से वाले देश को पानी की न्यूनतम मात्रा मिलने की गारंटी हो। इसका उद्देश्य सूखे मौसम या नदी का जलस्तर अचानक घटने पर पानी की आपूर्ति को सुरक्षित रखना है।

बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि सबसे सूखे मौसम में पर्याप्त पानी की गारंटी नहीं देती। उसकी आपत्ति यह भी है कि पानी बांटने का मौजूदा तरीका पुराने जलवैज्ञानिक हालात पर आधारित है। सूखे मौसम में नदी का प्रवाह अब ज्यादा अनिश्चित हो गया है। बांग्लादेश पर्यावरण से जुड़े प्रावधानों को भी अपर्याप्त मानता है। वह ऊपरी हिस्से में पानी की निकासी, नदी के स्वास्थ्य, बढ़ती लवणता और पारिस्थितिक प्रवाह को भी चर्चा में शामिल करना चाहता है।

**क्या फरक्का बैराज फिर बनेगा विवाद का केंद्र :** भारत-बांग्लादेश जल संबंधों में फरक्का बैराज लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत द्वारा बनाए गए इस बैराज का उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को हुगली नदी तंत्र की ओर मोड़ना है। बांग्लादेश में इसे लेकर लंबे समय से चिंता रही है कि इससे सूखे मौसम में नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम होता है। अनी ने कहा कि बांग्लादेशी लोग लंबे समय से फरक्का बैराज को 'मौत का जाल' मानते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि फरक्का के बाद भारत ने गंगा पर बैराज और करीब 900 तटबंध बनाए, जिससे दोनों देशों के संबंधों पर दबाव पड़ा।

**भारत का रुख क्या :** भारत का कहना है कि फरक्का बैराज बांध नहीं, बल्कि पानी को मोड़ने वाली संरचना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इसके द्वारों की व्यवस्था के जरिए गंगा के करीब 40,000 क्यूसेक पानी को फरक्का नहर में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पानी बांग्लादेश की ओर बहता रहता है। भारत यह भी कहता है कि समझौते के तहत जल प्रवाह का आंकड़ा संयुक्त नदी आयोग के जरिए बांग्लादेश के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है। बांग्लादेश और भारत के बीच 54 प्रमुख नदियां साझा हैं। गंगा दोनों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा-पार नदियों में से एक है। जल बंटवारे और नदी से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश संयुक्त नदी आयोग के जरिए बातचीत करते हैं।

**क्या भारत जल्द शुरू करेगा नई संधि पर बातचीत :** जुलाई में भारत की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर बिना और देरी के बातचीत शुरू करने को कहा था। समिति ने सिफारिश की थी कि बातचीत में नए जलवैज्ञानिक आंकड़ों, जलवायु अनुमानों और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। भारत सरकार ने फरवरी में संसद को बताया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर बांग्लादेश के साथ बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार सहित संबंधित पक्षों से मिले सुझावों को भारत का रुख तय करते समय ध्यान में रखा गया है। अनी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब इससे दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के लंबे समय से लंबित जल-बंटवारा समझौते को लेकर भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने भारत से अपने हितों के साथ बांग्लादेश के हितों को भी ध्यान में रखने की अपील की थी।

## नताली हार्प बनीं ट्रंप की सबसे भरोसेमंद साथी, कैमरे से दूर रहकर कैसे बढ़ा व्हाइट हाउस में असर

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कई ताकतवर लोग हैं, लेकिन 35 वर्षीय नताली हार्प की भूमिका अलग नजर आती है। वह कैमरे के सामने बोलने वाली अधिकारी नहीं हैं, फिर भी ट्रंप के आसपास लगातार दिखाई देती हैं। ओवल ऑफिस से लेकर मरीन वन तक वह राष्ट्रपति के साथ रहती हैं। खास तौर पर प्रेस सचिव रहीं केरोलिन लेविट की विदाई के बाद व्हाइट हाउस में हार्प की अहमियत और बढ़ने की बात सामने आई है।

**नताली हार्प को ह्यूमन प्रिंटर क्यों कहा जाता है :** हार्प ट्रंप के लिए लगातार जानकारी जुटाने, विश्व नेताओं से संदेशों के आदान-प्रदान और सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करने में मदद करती हैं। वह देर रात तक राष्ट्रपति के साथ काम करती हैं और रविवार को भी छुट्टी नहीं लेने की बात सामने आई है। उनके पास एक पोर्टेबल प्रिंटर भी रहता है। इसी वजह से व्हाइट हाउस में उन्हें 'ह्यूमन प्रिंटर' कहा जाता है। वह ट्रंप तक सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया की जानकारी तुरंत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

**ट्रंप के साथ खतरनाक सफर में भी क्यों रहीं :** नताली की भूमिका उस समय भी चर्चा में आई जब वह एक बेहद गुप्त अभियान का हिस्सा बनीं। इस अभियान में हमले के खतरे के बीच ट्रंप और कुछ चुनिंदा लोगों को तुर्किये से सुरक्षित



निकालने की कोशिश की गई थी। इसके लिए विमान के कैटरिंग कंटेनर का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद हार्प की भूमिका ज्यादा लोगों की नजर में आई। ट्रंप के करीबी सहयोगियों के अनुसार, राष्ट्रपति के प्रति उनकी निष्ठा बेहद मजबूत है।

**ट्रंप से नताली का रिश्ता इतना खास कैसे बना :** हार्प की ट्रंप से नजदीकी का एक निजी कारण भी बताया जाता है। वह कैंसर से जूझ चुकी हैं। उनके अनुसार, ट्रंप की ओर से समर्थित 'राइट टू ट्राई' कानून ने उन्हें प्रयोगात्मक इलाज तक पहुंच दिलाने में मदद की और इससे उनकी जिंदगी बचाने में मदद मिली। ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि दूसरे कर्मचारी भविष्य में उनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन नताली ऐसा नहीं करेंगी। यही निजी अनुभव दोनों के बीच भरोसे की एक वजह माना जाता है। हाल ही में सामने आए पत्रों में नताली ने ट्रंप के प्रति अपनी बेहद गहरी निष्ठा जाहिर की थी।

## यूएनएससी में भारत की दो टूक: विकासशील देशों को मिले अधिक प्रतिनिधित्व, आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा

**संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी।** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के काम करने के तरीकों पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में भारत की राजदूत योजना पटेल ने देश का पक्ष रखा।उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में सार्थक योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को दस्तावेजों तक पहुंच के मामले में एक जैसे अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

**राजदूत योजना पटेल ने क्या कहा :** योजना पटेल ने कहा कि जो देश सीधे तौर पर किसी मुद्दे से जुड़े हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद के फैसले लेने की व्यवस्था में भी शामिल किया जाना चाहिए। खासकर शांति स्थापना से जुड़े सभी बड़े सवालों में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इनमें मिशन का काम क्या होगा और उसके लिए कितने संसाधन दिए जाएंगे जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज संख्या- 507 में उचित बदलाव किया जाना चाहिए। इसमें सुरक्षा परिषद की सहायक संस्थाओं के अध्यक्षों के नाम तय करने के लिए स्पष्ट और अंतिम समय-सीमा होनी चाहिए। यह समय-सीमा ऐसी होनी चाहिए, जिस पर कोई समझौता न हो सके।

**आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा :** भारत ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद को छोटे और सीमित राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का मंच नहीं बनना चाहिए। योजना पटेल ने कहा कि सुरक्षा परिषद में किसी देश की मौजूदगी का इस्तेमाल आतंकवादियों को वैध ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक कारणों के आधार पर आतंकियों को आतंकवादी सूची से हटाने या दूसरी संस्थाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निष्पक्ष मापदंड और समर्थन करने वाले दस्तावेज होना जरूरी है।

## अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, भागवत के यूएस दौरे पर यूएससीआईआरएफ सख्त; बोला- संघ नेताओं को न मिले सम्मान

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली सलाहकार संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान न दे और न ही उनके साथ किसी तरह की हाई-लेवल मीटिंग करे। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले आया है। वहीं, भारत पहले ही यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण और वैचारिक पूर्वाग्रह पर आधारित बताते हुए खारिज कर चुका है। आरएसएस नेताओं से दूरी बनाने की अपील यूएससीआईआरएफ के चेयरमैन



आसिफ महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक %अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन यानी ऐसा मुख्य संगठन बताया, जिसके सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। महमूद की ये टिप्पणियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ हफ्ते पहले सामने आई हैं। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग की ओर से आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन (एकता का उत्सव) में शामिल होने वाले हैं। आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध की मांग यूएससीआईआरएफ कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को, भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, हाई-लेवल मीटिंग या राजनयिक सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ यानी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। यूएससीआईआरएफ ने आसिफ महमूद और जीन मिल्स की इन टिप्पणियों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। महमूद ने आरएसएस को लेकर क्या कहा महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। यह भारत का एक मुख्य संगठन है, जिसके सहयोगी समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। अब आरएसएस नेता मोहन भागवत अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी उठाए सवाल एडवोकेसी ग्रुप हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि मोहन भागवत के दौरे को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क से जुड़े हिंसा के आरोपों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

## विदेशों का नया ट्रेंड भारत की पुरानी जीवनशैली है ब्रिटेन-अमेरिका के जेन-जी अपना रहे भारतीय साइलेंट वॉक

**लंदन, एजेंसी।** अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों में जेन-जी के बीच इन दिनों साइलेंट वॉकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसमें युवा मोबाइल फोन को दूर रखकर, ईयरफोन उतारकर और बिना संगीत या पॉडकास्ट सुने चुपचाप टहलते हैं। सोशल मीडिया पर इसे तनाव कम करने और मानसिक सुकून पाने के तरीके के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि भारतीयों के लिए यह तरीका उतना नया नहीं है, क्योंकि यहां मौन और एकांत में टहलने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है।

**क्या है साइलेंट वॉकिंग और युवा इसे क्यों अपना रहे हैं :** साइलेंट वॉकिंग का मतलब बिना किसी डिजिटल गतिविधि के पैदल चलना है। इस दौरान मोबाइल, संगीत, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक और सोशल मीडिया से दूरी बनाई जाती है। व्यक्ति केवल अपने कदमों, विचारों और



आसपास के वातावरण पर ध्यान देता है। लगातार फोन और इंटरनेट से जुड़े रहने वाली युवा पीढ़ी के लिए यह तरीका कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाने का अवसर देता है। इसे तनाव कम करने और मन को शांत करने के एक आसान तरीके के रूप में देखा जा रहा है। क्या भारत में यह परंपरा पहले से मौजूद है भारत में मौन और एकांत को मानसिक शांति से जोड़ने की परंपरा सदियों पुरानी है। मंदिरों की परिक्रमा, मौन व्रत और विपश्यना जैसे अभ्यासों में बाहरी शोर से दूरी बनाकर आत्मचिंतन पर जोर दिया जाता है। मंदिर परिसरों और पार्कों में चुपचाप टहलना भी भारतीय जीवनशैली का हिस्सा रहा है। इसलिए पश्चिमी देशों में साइलेंट वॉकिंग का बढ़ता चलन भारतीय नजरिए से किसी बिल्कुल नई चीज के बजाय पुरानी परंपरा के आधुनिक रूप जैसा दिखाई देता है।

**क्या भारतीय युवा भी इसे अपना रहे हैं :** भारत में भी युवा बिना ईयरफोन और मोबाइल में व्यस्त हुए सार्वजनिक जगहों पर टहलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली का लोधी गार्डन, बंगलूरू का कब्बन पार्क और मुंबई का मरीन ड्राइव ऐसे स्थान हैं, जहां लोग चहलकदमी करते हैं। हालांकि भारत में इसे हमेशा साइलेंट वॉकिंग के नाम से नहीं जाना जाता। पश्चिम में इसके लिए एक नया नाम और सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है, जबकि भारत में इसके पीछे की आदत और विचार लंबे समय से मौजूद हैं।

**2023 में सोशल मीडिया पर कैसे लोकप्रिय हुआ यह नाम :** साइलेंट वॉकिंग की अवधारणा पुरानी है, लेकिन इसका नाम 2023 में सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ। टिकटॉक क्रिएटर मैडी माओ ने बिना फोन, संगीत और पॉडकास्ट के 30 मिनट टहलने का अपना अनुभव साझा किया था। इसके बाद यह तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। धीरे-धीरे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और बेल्जियम समेत कई पश्चिमी देशों के युवाओं ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। साइलेंट वॉकिंग के बढ़ते चलन में डिजिटल दुनिया से थोड़ी देर दूरी बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है।

## ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई: ट्रंप ने दी धमकी, मदद करने वाले देशों को चेताया; क्या बढ़ेगा तनाव

**वाशिंगटन डीसी, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था। लेकिन उसने इसे गंवा दिया।

ट्रंप ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल गई हैं। ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है।

**ईरान की मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई :** ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें वित्तीय संस्थान, कारोबार, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, नकद लेनदेन, एक्सचेंज हाउस, जहाजों के पंजीकरण और ईरान की मदद करने वाली छिपी हुई (शेल) कंपनियों को तुरंत रोकने की बात कही।

**सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ आने की अपील :** ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले का दिन बताया। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से ईरान को अलग-थलग करने और उसके खतरे को खत्म करने में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है।



उन्होंने दावा किया कि ये ऐतिहासिक कदम ईरान को और दुनियाभर में आतंक फैलाने की उसकी क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा।

**अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया :** अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पिछले हफ्ते इसी तरह बयान दिया था। बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशें बढ़ाएगा। इस रणनीति में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय %ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी% नाम से प्रतिबंध अभियान भी चला रहा है। इसका मकसद लक्षित कार्रवाई के जरिये ईरान के पैसे जुटाने के स्रोतों को बंद करना है। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के साथ हुई। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने ईरान को सैन्य उपकरण और ड्रोन से जुड़ी तकनीक दी है। वहीं, चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। चीन ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते बनाए रखे हैं और उसे कूटनीतिक समर्थन भी दिया है।

## कौन हैं अमेरिका की एफडीए प्रमुख बनने जा रहीं हेइडी ओवरटन, ट्रंप ने किया नामित, विवादों से भी रहा है नाता

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. हेइडी ओवरटन को खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए का अगला आयुक्त बनाने के लिए नामित किया है। अगर अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है, तो वह इस बेहद महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। एफडीएअमेरिका में दवाओं, वैक्सीन, चिकित्सा उपकरणों और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और नियमन से जुड़े बड़े फैसले करता है। ओवरटन फिलहाल व्हाइट हाउस के घरेलू नीति परिषद में उपनिदेशक के पद पर हैं और ट्रंप प्रशासन की स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।

**ओवरटन की पढ़ाई और करियर कितना मजबूत :** हेइडी ओवरटन मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से मेडिकल की पढ़ाई की। इसके बाद जॉन्स हॉपकिन्स में जनरल सर्जरी का प्रशिक्षण लिया और क्लिनिकल जांच से जुड़ी उच्च शिक्षा भी हासिल की। ट्रंप प्रशासन में आने से पहले वह कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में मुख्य नीति अधिकारी के रूप में काम कर चुकी हैं। यानी उनका अनुभव केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य नीति और राजनीतिक प्रशासन से भी जुड़ा रहा है।

**ट्रंप के भरोसेमंद लोगों में कैसे शामिल हुईं :** दूसरे कार्यकाल में ओवरटन ट्रंप की कई स्वास्थ्य योजनाओं में उनके साथ दिखाई दी हैं। दवा की कीमत कम करने, नई दवाओं को तेजी से मंजूरी देने और स्वास्थ्य नीति में बदलाव से जुड़े कई कार्यक्रमों में उन्होंने भूमिका निभाई है। ट्रंप ने उनके नाम की घोषणा करते हुए उन्हें बेहद सक्षम और भरोसेमंद अधिकारी बताया तथा तेज इलाज, चिकित्सा नवाचार और दवाओं की कम कीमत जैसे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने भी ओवरटन के फैसले लेने की क्षमता और प्रशासनिक अनुशासन की तारीफ की है।

**वैक्सीन नीति को लेकर क्यों उठे सवाल :** ओवरटन की नियुक्ति का



सबसे विवादित पक्ष उनकी वैक्सीन नीति से जुड़ी भूमिका है। हाल में वह उस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ खड़ी थीं, जिसमें बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी। इसमें खसरा, कण्ठमाला और रूबेला यानी एमएमआर वैक्सीन को अलग-अलग टीकों में बांटने की योजना भी शामिल थी। चिकित्सा जगत के कई लोगों ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से ओवरटन की एफडीएमें संभावित भूमिका को लेकर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहस तेज हो गई है।

**गर्भपात की दवाओं पर क्या है ओवरटन का रुख :** ओवरटन गर्भपात की दवाओं को लेकर भी सख्त रुख रखती हैं। वह ऐसी दवाओं की उपलब्धता और ऑनलाइन इस्तेमाल से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था की आलोचना कर चुकी हैं। अगर सीनेट से उनकी नियुक्ति मंजूर होती है, तो स्त्रष्ठ के सामने गर्भपात की दवाओं से जुड़े नियमों की समीक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अमेरिका में गर्भपात को लेकर पहले से ही राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर ओवरटन के फैसलों पर खास नजर रहेगी।

**एफडीएको संभालते ही किन बड़ी चुनौतियों का सामना होगा :** ओवरटन ऐसे समय एफडीए की कमान संभाल सकती हैं, जब संस्था पहले ही नेतृत्व और कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। पूर्व आयुक्त डॉ. मार्टी मकारी ने मई में पद छोड़ दिया था। उनके कार्यकाल में ई-सिगरेट, गर्भपात की दवाओं और नई दवाओं की मंजूरी जैसे मुद्दों पर विवाद रहे। एफडीए में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के जाने से भी संस्था पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में नई प्रमुख से प्रशासनिक स्थिरता और जनता का भरोसा बहाल करने की उम्मीद होगी।

**क्या दवाओं की मंजूरी का तरीका भी बदल सकता है :** एफडीए की एक बड़ी जिम्मेदारी नई दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की जांच तथा मंजूरी देना है। ट्रंप प्रशासन तेज मंजूरी और चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा देने की बात करता रहा है। दूसरी ओर, एफडीए से जुड़े वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देते हैं। ओवरटन को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। खासकर दुर्लभ बीमारियों की दवाओं, जैव-तकनीकी उत्पादों और नई चिकित्सा तकनीकों से जुड़े फैसले उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौती होंगे। एफडीए केवल दवाओं और वैक्सीन तक सीमित नहीं है। खाद्य सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने अल्ट्राप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं।


स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## माता-पिता पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे : रोहिणी आचार्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को जवाब देने के बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपने रुख को स्पष्ट किया है। रोहिणी ने साफ कहा है कि उनके माता-पिता, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, पर यदि कोई अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो वह उसका जवाब उसी भाषा में देंगी। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनके लिए माता-पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि माता-पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी होने पर उनकी ओर से जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा, जिस भाषा में टिप्पणी की गई होगी। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मांझी ने किसी अन्य व्यक्ति के बयान के संदर्भ में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बारे में टिप्पणी की थी, जबकि उस बयान से उनके माता-पिता का कोई लेना-देना नहीं था। रोहिणी के अनुसार, मांझी ने विषय से हटकर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर टिप्पणी की, जिसे उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित और ओछी टिप्पणी बताया। रोहिणी ने कहा कि एक बेटी होने के नाते ऐसी टिप्पणी का जवाब देना उनके लिए स्वाभाविक था। अपनी भाषा की मर्यादा पर बात करते हुए रोहिणी ने कहा कि वह इसका बखूबी ख्याल रखना जानती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अपनी बात मर्यादा के दायरे में रखते हैं, वह उनकी मर्यादा का भी सम्मान करती हैं। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों का भी जिक्र किया, जिनमें उनके किसी व्यक्ति के बचाव में खड़े होने या किसी का बचाव करने की बात कही जा रही थी। इस तरह के नरेटिव को सिरे से खारिज करते हुए रोहिणी ने कहा कि वह पल-पल अपनी राय बदलने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उनके अनुसार गलत था या है, वह गलत ही रहेगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। उन्होंने कहा कि वह अपने स्टैंड, राय और विचार पर दृढ़ता से कायम रहने वालों में से हैं और आगे भी इसी तरह अपने विचारों पर कायम रहेंगी। रोहिणी के इस पोस्ट को हालिया राजनीतिक बयानबाजी के बीच उनके रुख को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

## राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर मचा सियासी घमासान, फडणवीस और सपकाल आमने-सामने

मुंबई (एजेंसी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पुणे दौरे से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन सपकाल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। फडणवीस ने दावा किया था कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम केवल कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों के छात्रों तक ही सीमित रहेगा, जबकि सपकाल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सपकाल ने स्पष्ट किया कि 22 अगस्त को एआईएसएसएमएस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम सभी छात्रों के लिए खुला रहेगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पुणे पहुंचे सपकाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि यह छात्राओं के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम होगा। उन्होंने पुणे के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा, यह कार्यक्रम पुणे में हो रहा है, जो लड़कियों की शिक्षा की नींव रखने वाली सावित्रीबाई फुले और जीजामाता की भूमि है, जिन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य का मंत्र दिया। फडणवीस ने नागपुर में बयान देते हुए कहा था कि उनकी जानकारी के अनुसार, गांधी कांग्रेस नेताओं द्वारा संचालित कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों के साथ ही बातचीत करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक नियंत्रित माहौल में होने वाला बताया और आशंका जताई थी कि यह खुले संवाद के बजाय एकतरफा भाषण हो सकता है। हालांकि, सपकाल ने फडणवीस के इस दावे पर कोई पाबंदी होने से साफ इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह जुबानी जंग राहुल गांधी के पुणे में छात्रों के साथ सीधे जुड़ने के प्रयास से पहले राजनीतिक माहौल को गरमा रही है।

## गुजरात में जहरीली शराब का कहर, मृतकों की संख्या 11, अस्पताल में 20 लोगों का इलाज

भावनगर (एजेंसी)। गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली और नकली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। करीब 20 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के बाद भावनगर शहर और आसपास के इलाकों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नकली शराब को लोकप्रिय आईएमएफएल ब्रांड की डुप्लीकेट बोतलों में भरकर बेचा गया। पुलिस के अनुसार, शराब की कुछ खेप मध्य प्रदेश से भावनगर पहुंचने की आशंका है। मामले में पुलिस ने अब तक कई संदिग्ध शराब तस्करों को हिरासत में लिया है. बड़ी संख्या में नकली शराब की बोतलें जब्त की हैं। 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी है। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री के मामले सामने आने से पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

# युवाओं से संवाद बढ़ाएं और साइलो तोड़ें, पीएम मोदी ने दिए अधिकारियों को खास निर्देश

### -तीसरी उच्चस्तरीय सचिव बैठक में दीर्घकालिक सोच, एआई-मानव समन्वय, डेटा साझाकरण और पोर्ट-लेड विकास पर दिया जोर

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे की समीक्षा की। बैठक में बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा सुशासन से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर समन्वित कार्य संस्कृति विकसित करने और युवाओं के साथ सरकार का संवाद मजबूत बनाने का आह्वान किया।

बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बुधवार को हुई इस हाईलेबल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों को केवल मौजूदा चुनौतियों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ नीति निर्माण और क्रियान्वयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में दूरदर्शी सोच अत्यंत आवश्यक है।
विभागों के बीच तालमेल की कमी को 'साइलो' की समस्या बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक ढांचे की नहीं, बल्कि कार्यशैली और सोच की चुनौती भी है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का स्वामित्व लेने तथा अपनापन और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ काम करने को कहा। कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय मंत्रालयों ने जिस प्रभावी समन्वय का प्रदर्शन किया था, उसे सरकार की स्थायी कार्य संस्कृति बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि एआई का अधिकतम उपयोग किया जाए, लेकिन मानवीय निर्णय क्षमता और विशेषज्ञता को उसके साथ जोड़े रखना आवश्यक है। इसी प्रकार उन्होंने डेटा को देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए विभागों के बीच डेटा इंटरऑपरेबिलिटी और बेहतर साझाकरण की जरूरत रेखांकित की, ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।
बैठक में विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और युवाओं के साथ सरकारी विभागों के संवाद को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी की भागीदारी से नीति निर्माण में नवाचार और अपरंपरागत विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा। रक्षा अनुसंधान, जहाज निर्माण, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट तथा विनिर्माण एवं निर्यात उद्योगों की बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर भी उन्होंने मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अधिक अनौपचारिक संवाद स्थापित करने, विभिन्न कैडरों और विभागों के बीच मजबूत नेटवर्क विकसित करने तथा पूरी सरकार में टीम भावना और समन्वित दृष्टिकोण को और सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया।

## सड़कों पर तड़तड़ाने लगी गोलियां और लहराने लगे हथियार, देहरादून में छात्र गुटों का खूनी तांडव

देहरादून (एजेंसी)। शिक्षा और शांति के लिए विख्यात देहरादून की पहचान को गुरुवार को छात्र गुटों के खूनी संघर्ष ने झकझोर दिया। पलनगर इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर करीब तीन किलोमीटर तक फैल गया, जिसमें पिस्टल और लाठी-डंडों का जमकर इस्तेमाल हुआ। दिनदहाड़े हुए इस तांडव में छह राउंड फायरिंग हुई और एक युवक घायल हो गया, जिससे शांत शहर में दहशत फैल गई। यह घटना देहरादून के बदलते मिजाज की एक खतरनाक तस्वीर पेश करती है, जिसे अब तक सुकून और शिक्षा के केंद्र के तौर पर जाना जाता रहा है। सबसे गंभीर बात यह रही कि यह हिंसा किसी सुनसान कोने में नहीं, बल्कि शहर की मुख्य सड़कों पर हुई, जहाँ एक पक्ष कार में तो दूसरा बाइकों से पीछा कर रहा था। रास्ते में चार पुलिस पिकेट होने के बावजूद यह विवाद एक स्थान पर नहीं रुका, बल्कि शहर के भीतर दौड़ता हुआ दूसरी जगह पहुंचा। यह सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं है, यह उस गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है जब छात्र गुटों की रंजिश कैंपस की सीमाओं को लांघकर सड़क पर उतर आती है और विवाद का जवाब तर्क से नहीं, बल्कि हथियारों से दिया जाता है। देहरादून में छात्र गुटों के बीच हिंसा का यह पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले हुए दिव्यांशु जटराणा हत्याकांड ने भी छात्र विवादों के खूनी अंजाम की भयावहता दिखाई थी। उस घटना के बाद छात्र गतिविधियों पर निगरानी और संस्थानों के साथ समन्वय की बातें कही गईं थीं, लेकिन गुरुवार की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का असर सिर्फ घटना के बाद ही दिखाई देता है। हजारों बाहरी छात्र देहरादून में किराये के मकानों और छात्रावासों में रहते हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों पर पुलिस सत्यापन और निगरानी का तंत्र कमजोर दिखता है।

## जयपुर में भाजपा और सीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव, रांका को ग्रामीणों ने खदेड़ा

### -सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे थे सीजेपी कार्यकर्ता

**जयपुर, एजेंसी।**
राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांव रामपुरा-कंवरपुरा में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर भाजपा समर्थक ग्रामीणों और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं के बीच खासा विवाद हो गया। दरअसल सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ एक सरकारी स्कूल की असल स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने उनके स्कूल में प्रवेश का विरोध कर दिया। कहा-सुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीणों के विरोध के बाद रांका और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को मौके से लौटना पड़ा। रिपोर्टों में वाहनों के शीशे टूटने और पथराव की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, घटना को लेकर दोनों पक्षों के आरोप अलग-अलग हैं। रांका ने आरोप लगाया कि उनके साथियों के साथ मारपीट भाजपा समर्थकों ने की, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वे गांव के सरकारी स्कूल में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते।
मौजूदा विवाद की जड़ स्कूल भवन की खराब हालत बताई जा रही है। सीजेपी का दावा है कि बच्चे जर्जर भवन के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन के लिए सरकारी बजट स्वीकृत हो चुका है और वे स्वयं इसके निर्माण को लेकर प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर भी नजर है।

## मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई भी कार्य समिति के अध्यक्ष के फैसले के बिना नहीं हुआ

### -पूर्व महासचिव चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्र को लेकर नौ पन्नों का पत्र जारी कर लगाए आरोप

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद एक बार फिर सामने आया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे नृपेंद्र मिश्र को लेकर नौ पन्नों का पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर परिसर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और ट्रस्ट की व्यवस्था तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय ने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण से जुड़े अहम फैसलों में नृपेंद्र मिश्र की भूमिका बेहद प्रभावशाली रही और उनकी पसंद के लोगों को समिति में शामिल किया गया। चंपत राय के मुताबिक मंदिर निर्माण समिति की बैठकों में फैसले लिए जाते थे, लेकिन कई मामलों में बाद में बदलाव कर नृपेंद्र मिश्र के निर्णयों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने दावा किया कि मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य समिति के अध्यक्ष के फैसले के बिना नहीं हुआ।
पत्र में यह भी कहा गया है कि उनकी पसंद के कुछ लोग समिति में शामिल किए गए, जिनमें से कुछ छह साल में केवल एक-दो बार ही अयोध्या आए हैं।
चंपत राय ने कहा कि नृपेंद्र मिश्र के सुझाव पर लार्सन एंड टूब्रो को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को परियोजना प्रबंधन सलाहकार बनाया गया। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा को 1986 में अशोक सिंघल ने चुना था और बाद में उन्हें ही निर्माण योजना में बनाए रखा। परिसर के अन्य भवनों के डिजाइन का काम नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म को दिया गया। चंपत राय ने पत्र में राम जन्मभूमि विवाद के इतिहास और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने तक की घटनाओं का भी उल्लेख किया।
चंपत राय ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन 75 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने लगे। महाकुंभ में यह संख्या तीन लाख से ज्यादा थी। श्रद्धालुओं के लिए आठ अलग-अलग लाइनें बनाई गई हैं। ट्रस्ट के बैंक खातों में चेकबुक का इस्तेमाल नहीं होता और भुगतान बैंक ट्रांसफर से किए जाते हैं। खातों का आंतरिक और वैधानिक ऑडिट भी कराया जाता है।

बता दें राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 6 जुलाई को उन्होंने ट्रस्टी अनिल मिश्र को लेकर भी आरोप लगाए थे। अब नृपेंद्र मिश्र पर जारी नौ पन्नों के पत्र से मंदिर निर्माण और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद फिर चर्चा में आ गया है।

## बैठक में शामिल नहीं होने का आग्रह हाई कमान से किया था: चन्नी

### सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल नहीं होने पर चन्नी ने दी सफाई

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को खुलासा किया कि उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल न होने के लिए पार्टी आलाकमान से विशेष अनुमति ली थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक की जगह, उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी परीक्षा में शामिल होना था, जिसे वे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। चन्नी का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सीडब्ल्यूसी की बैठक बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई थी, जिसमें देश के ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।
एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी चन्नी का अकादमिक समर्पण उल्लेखनीय है। उन्होंने बताया कि यह उनके लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री की अंतिम परीक्षा थी, जिसे छोड़ना उनकी डिग्री में एक साल की देरी और उनके भावी शोध कार्यों को प्रभावित करता। चन्नी ने पहले ही पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी की है और अब वे सार्वजनिक नीति में सुधार के क्षेत्र में आगे शोध करने में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर मैं परीक्षा नहीं देता तो मेरी डिग्री में एक साल की देरी हो जाती और इस वजह से जिस शोधकार्य को मैं करना चाहता हूं, उसमें भी देरी हो जाती। उन्होंने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बारे में कहा कि यह लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री की आखिरी परीक्षा थी और इसके बाद वे नीति सुधारों पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए पंजाब विश्वविद्यालय से ही जुड़ेंगे।

सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य वरिष्ठ नेताओं और विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा कांग्रेस-शासित राज्यों के सभी चार मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में हुई थी। इस लंबी बैठक में प्रश्नपत्र लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तराखंड में अपने कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण के मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पार्टी के कई सहयोगियों से समर्थन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अच्छा लिखने और अच्छा दिखने वालों ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। हालांकि, खरगे ने इस घटना पर मजबूती से आवाज उठाने और भाजपा-आरएसएस को घेरने के लिए कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई की सराहना की।
कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया था कि सीडब्ल्यूसी ने खरगे की सभा के स्थल के कथित शुद्धिकरण की घटना की कड़ी निंदा की है। वेणुगोपाल ने इस घटना को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और मांग की कि मोदी को इस संवेदनशील मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। यह घटना मल्लिकार्जुन खरगे के उत्तराखंड दौरे के बाद उनके रैली स्थल को शुद्ध करने की थी, जिसे दलित अध्यक्ष के प्रति अपमानजनक और जातिवादी रवैये के रूप में देखा गया।

## इथेनॉल नीति से महंगी हुई चीनी, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
चीनी सहित अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच, कांग्रेस ने मोदी सरकार की ई20 नीति को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने की यह नीति सड़कों पर वाहन मालिकों और रसोई में आम जनता दोनों की जेब पर भारी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे न केवल खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि वाहनों का माइलेज भी कम हुआ है और उनसे जुड़ी समस्याएं भी सामने आ रही हैं।
जयराम रमेश ने 21 फरवरी को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि गन्ने और अनाज का इथेनॉल उत्पादन में जाना खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। उनके अनुसार, लगभग 25 लाख टन चीनी-योग्य गन्ना इथेनॉल में चला गया, जिसके परिणामस्वरूप केवल पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमतें 48 रुपये से बढ़कर 67 रुपये प्रति किलो हो गईं। गुड़ भी 50 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि चावल और मक्के के आटे में क्रमशः 16 और 11 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। पशु आहार के दाम भी 10.34 फीसदी बढ़े हैं।

कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी और इथेनॉल मिश्रण से लागत कम होने के बावजूद पेट्रोल के दामों में कोई कमी क्यों नहीं की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार ई20 नीति के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कांग्रेस कार्यसमिति ने 19 अगस्त को ही ई 20 के कारण कम माइलेज, वाहनों की कंपैटिबिलिटी से जुड़े जोखिम, उपभोक्ताओं के सीमित विकल्पों और पर्यावरणीय क्षति के सवालों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। कांग्रेस ने तत्काल इस नीति की समीक्षा करने और उपभोक्ताओं को बिना इथेनॉल वाले ईंधन का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है, क्योंकि गाड़ी भी महंगी और रसोई भी वाली ऐसी जनविरोधी ईंधन नीति देश को स्वीकार्य नहीं है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात को मंजूरी दी है, जो बीते एक दशक में ऐसा पहला मौका है। दिल्ली में 21 अगस्त को चीनी 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है।

## पानी समुद्र में बहे और किसान बूंद-बूंद को तरसे ये ठीक नहीं : शाह

### - दो राज्यों के जल विवाद पर अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंतरराज्यीय जल विवादों को बातचीत से सुलझाने के सुझाव को दक्षिण भारत के राज्यों ने समर्थन दिया है। गुरुवार को दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा, जहाँ लोकसभा सीटों के परिसीमन पर भी गहन चर्चा हुई। अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अपने राज्य के हितों की रक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर पानी की कमी के कारण किसी राज्य को वर्षों तक वंचित रहना पड़े और पानी समुद्र में बहता रहे, तो यह किसी के हित में नहीं है।
शाह ने भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र से कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे कई जलमार्ग भी विकसित हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे के आठ में से पांच ब्रिटिश-पूर्व विवादों के सफल समाधान का उदाहरण दिया, जहां पांच महीने पहले अंतिम समझौता हुआ था। हालांकि, बैठक में लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा विवाद का विषय बन गया। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान की आशंका जताई। कर्नाटक और तमिलनाडु ने मांग की कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें अगले 25 वर्षों तक बनी रहें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने परिषद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से 1971 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाए रखने और महिलाओं के आरक्षण को मौजूदा सीटों के भीतर ही लागू करने की मांग की।
अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी चिंताओं के साथ सामने आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को मेकेदातु बांध परियोजना से उनके हितों की रक्षा का आश्वासन दिया, हालांकि तमिलनाडु के मंत्री ने स्पष्ट किया कि कावेरी जल विवाद पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम के रास्ते आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और अमरावती-बेंगलुरु-चेन्नई ट्रांजिट नेटवर्क का प्रस्ताव रखा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे के मामलों को गृह मंत्रालय के साथ सुलझाने पर सहमति जताई। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहकारी संघवाद पर जोर दिया। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमरका ने कृष्णा नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों की सुरक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहयोग मांगा, जबकि पुडुचेरी ने सालभर पानी की उपलब्धता के लिए केंद्र और तमिलनाडु से सहयोग की अपील की।